राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • मंगलवार • 10 जून • 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कुल की प्रशंसा करने से क्या लाभ? शील ही (मनुष्य की पहचान का) मुख्य कारण है। क्षुद्र मंदार आदि के वृक्ष भी उत्तम खेत में पड़ने से अधिक बढ़ते-फैलते हैं

-मृच्छकटिक

कब बुझेगी आग

मणिपुर में इम्फाल जिले के क्वाकेथेल सिंगजामेई में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई। तुलिहाल के उप-विभागीय कलेक्टर कार्यालय को जलाये जाने से सरकारी रिकॉर्ड नष्ट हुए और इमारत को भी नुकसान हुआ। मैतई संगठन अरम्बाई तेंगोल के नेता कानन सिंह समेत चार की गिरफ्तारी का बाद निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रात भर मशाल जुलूस निकाला। महिला समूहों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों की आवाजाही में अवरोधक बनाए, सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगा दिए और जगह-जगह टायरों को जलाया। हिंसक होते प्रदर्शन को रोकने के लिए इम्फाल पश्चिम व पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। मई 2023 से मैतई और कुकी के दरम्यान

चलल रही जातीय हिंसा में ढाई सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य विधानसभा के निलंबन के बाद से 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन के अधीन है। स्थानीय जनता तत्काल सरकार के गठन की मांग कर रही है। सीबीआई विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते गिरफ्तारियां भी कर रही है। केंद्र द्वारा जून 2023 में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। उसी साल अगस्त में सबसे बड़ी अदालत ने राज्य की संवैधानिक मशीनरी के पूरी तरह ध्वस्त होने की बात भी की थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार का रवैया मणिपुर को लेकर बेहद शर्मनाक है। बेघर हो रही स्थानीय जनता आस-पास के राज्यों में पलायन करे मजबूर है। रोजगार संकट बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चरमारा चुकी है। कुकी और मैतई संघर्ष नया नहीं है मगर उसे सुलझाने या शांत करने में केंद्र को जैसी महती भूमिका निभानी चाहिए। उसके प्रति वह उपेक्षा भाव अपनाए है। पूर्वोत्तर राज्यों का यह आरोप है कि उनको समुचित सम्मान नहीं दिया जाता और हमेशा उनके साथ पक्षपात भरा बर्ताव होता है। केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे के बावजूद उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री वहां का दौरा करें मगर विपक्ष के लगातार कटाक्ष के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर की अशांति पर कभी विचार तक नहीं प्रकट किए। प्रदेशवासियों की संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए शांति बहाली के प्रति कड़े कदम उठाने चाहिए। देश की अखंडता के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही गलत संदेश दे सकती है। जरूरी है, केंद्र को अपने रवैये में लचीलापन लाते हुए दूरदर्शितापूर्ण नजर आना होगा।

बेहद गरीबी से उबार

भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1 प्रतिशत से एक दशक में तेजी से घट कर 2022-23 में 5.3 प्रतिशत रह गई। यह जानकारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से मिली है। हालांकि विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करके तीन डॉलर प्रति दिन कर दिया है। बेशक, यह रिपोर्ट हौसला देती है। खासकर मौजूदा वैश्विक के मद्देनजर किसी भी देश के लिए इस प्रकार का आकलन खासा उत्साहवर्धक होता है। भारत विकासशील देश है, और अपनी आयोजना में शुरू से से ही गरीबी उन्मूलन का प्राथमिकता देता रहा है। गरीबी से अपने लोगों को उबारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं ताकि आम जन के आर्थिक हालात बेहतर से बेहतर हो सकें। सत्तर के दशक में 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर चुनाव तक लड़ा गया। जीता भी गया। बेशक, सरकार की तमाम प्राथमिकताओं और चिंताओं के केंद्र में गरीबी

उन्मूलन रहा है। इसके नतीजे भी अच्छे मिले, लेकिन कुछ समस्याएं बराबर बनी रहीं जिनके चलते गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। एक तो यह हुआ की आर्थिक विकास के लाभ कुछ वर्गों तक ही सीमित रह गए। इसके चलते आर्थिक असमानता की समस्या उभरी जिससे पार पाने के लिए आज जूझना पड़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि गरीबी से पार पाने में खासी सफलता मिली है। इस बात की ताकीद शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे मानकों में देश के बेहतर प्रदर्शन से होती है। गरीबी कम करने में हम कमजोर नहीं पड़े हैं। और अब तो विश्व बैंक भी इसकी तस्दीक कर रहा है। विश्व बैंक ने अप्रैल में भारत पर अपने 'गरीबी और समानता संक्षिप्त' में कहा था कि अत्यधिक गरीबी (प्रति दिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन) 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घट क 2022-23 में 2.3 प्रतिशत हो गई जिससे 17.1 करोड़ लोग इस रेखा से ऊपर आ गए। बेशक, गरीबी उन्मूलन के प्रयास आजाद भारत के किसी भी कालखंड में शिथिल नहीं पड़ने पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ वैश्विक हालात पर निर्भर करता है। वैश्विक जोखिम आज कहीं ज्यादा नकारात्मक हैं। अमेरिका जैसे देशों में नीतिगत बदलाव, कई देशों में युद्ध के हालात ने वैश्विक परिदृश्य को तनावपूर्ण बना दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक इतने मजबूत हैं कि भारत अपने लोगों के हालात बेहतर करने में जरूर सफल होगा।

पुस्तकालय विज्ञान/डॉ. प्रितम भि. गेडाम

डॉ. कुमार का योगदान अतुलनीय

जब हम देश में पुस्तकालयों के विकास की बात करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महानतम कार्य किए हैं। डॉ. पीएसजी कुमार, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही पुस्तकालय सूचना विज्ञान क्षेत्र के विकास में समर्पित कर दिया।

देश भर में पुस्तकालय सूचना विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत लोगों का सपना रहा कि डॉ. पीएसजी कुमार के मार्गदर्शन में कुछ सीखने को मिले। लोग उन्हें पुस्तकालय सूचना विज्ञान विषय का विश्वकोश कहते हैं। वे गुणों की खान थे, पुस्तकालय क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी और विकास संबंधित कार्यप्रणाली उनके मस्तिष्क में छपी हुई थी। अपने उत्कृष्ट योगदान और गुणवत्तापूर्ण कार्य के कारण डॉ. पीएसजी कुमार को पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉ. एसआर रंगनाथन के समकक्ष माना जाता है। डॉ. कुमार ने अपने जीवन का अधिकांश कार्यकाल नागपुर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग में बिताया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, विचारशील, बुद्धिजीवी, मृदुभाषी, समय के पाबंद और कार्य के प्रति अक्सर तत्पर रहते थे। डॉ. कुमार के अथक प्रयासों के कारण ही विदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए स्नातकोत्तर पदवी पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

वे पुस्तकालय विज्ञान की दुनिया से जुड़े विषयों की व्यापकता और विविधता को समाहित करते रहे। उन्होंने अपनी निजी संग्रह के पुस्तकों की बहुमूल्य पूंजी संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती के पुस्तकालय को भेंट कर दी। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय पर व्याख्यान एवं स्थापना के लिए नागपुर विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये का दान दिया। उनके कार्य से प्रेरित होकर डॉ. पीएसजी कुमार लाइब्रेरी फाउंडेशन बनाया गया है। पुस्तकालय सूचना विज्ञान विषय के विकास और समृद्धि के लिए वे जीवनभर प्रयत्नशील और कर्मशील रहे। उनकी इसी धरोहर को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते जाना हम सबका कर्तव्य है। आज वो भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन पुस्तकालय सूचना विज्ञान विषय में उनके अमूल्य योगदान को यह क्षेत्र हमेशा याद रखेगा और ऋणी रहेगा।

देश की छवि से घात

राहुल बनाम चुनाव आयोग

अवधेश कुमार

एक दृश्य की कल्पना करिये। अगर भारत की छवि ऐसी बन जाए कि यहां सरकार संविधान को ताक पर रख अपने अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, आयोग फर्जी तरीके से मतदाता सूची बनाता है, मतदान के आंकड़े गलत जारी करता है तथा सरकार के पक्ष में मतदान परिणाम लाता है तो क्या होगा? यानी पूरी सरकार अनैतिक है जो धांधली के आधार पर संवैधानिक शक्तियों और संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में बनी हुई है। एक देश के रूप में भारत की साख को नष्ट करने का इससे गंदा अभियान कुछ नहीं हो सकता।

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अनेक नेता, एक्टिविस्ट मीडिया के कुछ चेहरे लंबे समय से यही अभियान चला रहे हैं। इसके साथ न्यायपालिका सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं को भी इसी तरह संदिग्ध बनाने की रणनीति साफ दिखाई देती है। इन सबके लिए सुविधाओं के अनुसार एकपक्षीय तथ्य और आंकड़े दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट बताते हुए लिखा है कि यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा, जहां-जहां भारतीय भाजपा हार रही होगी। 'अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें :

महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लोक सभा और विधानसभाओं के हाल में हुए चुनाव के लिए समेकित, डिजिटल, मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम पांच बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। पहली बार पढ़ने पर अवश्य इसमें सनसनाहट पैदा होती है। किंतु चुनाव प्रक्रिया में निचले स्तर भी जुड़ी राजनीति के साधारण व्यक्ति के गले कोई बात नहीं उतरेगी। वैसे ये आरोप नये नहीं हैं। पिछले वर्ष भी चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों का उत्तर दिया था। जिन्हें तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं और संपूर्ण भारत की सत्ता को फासिस्ट, अनैतिक और सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन कर कब्जा करने वाला साबित कर विश्व भर में बदनाम करने का जिनका सपना हो वे ऐसे ही खंडित हो चुके आरोपों को बार-बार दोहराएंगे। निर्वाचन आयोग ने छह राष्ट्रीय पार्टियों से बातचीत के लिए अलग-अलग आमंत्रित किया था। कांग्रेस को छोड़कर शेष सभी चुनाव अधिकारियों से मिले, अपना पक्ष रखा तथा उत्तर सुना। केवल कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा 15 मई को प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लिया था। चुनाव आयोग शायद फिर देश के सामने तथ्य रखे। मीडिया में आयोग के हवाले से जो

वक्तव्य आया है उसमें कहा गया है कि किसी के द्वारा प्रसारित कोई भी गलत सूचना चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी तथा चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह सही है कि देश में चुनावी प्रक्रिया में जितनी संख्या में सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल , पत्रकार, आम लोग लगते हैं ऐसे बयान उन सबके परिश्रम को निष्फल करने वाला तथा उनके अंदर गुस्सा और निराशा पैदा करना है।

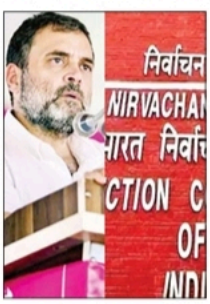

चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर ही एकपक्षीय अभियान चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती रही है। इसके विपरीत राहुल और विरोधी ऐसी छवि बना रहे हैं मानो पहले नियुक्ति दूसरे तरीके से होती थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने उसे पलट दिया है। सच यह है कि इसमें विपक्ष के नेता का प्रावधान डालकर ज्यादा विमर्शमूलक बनाया गया है। 25 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा हुई। राजनीति में रहते हुए राजनीतिक सत्ता को ही अविश्वसनीय बना देना किस तरह की लोकतांत्रिक सोच का परिचायक है? अब आएं महाराष्ट्र चुनाव संबंधी अन्य आरोपों पर। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या वृद्धि असामान्य है। बोगस मतदाता शब्द प्रयोग उन्होंने इस आधार पर किया कि 5 वर्षों में 31 लाख मतदाता तथा केवल अंतिम पांच महीना में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। बढ़े हुए 40 लाख 81 हजार 229 मतदाताओं में से 26 लाख 46 हजार 608 युवा मतदाता थे। पुराने आंकड़े देखिए। 2014 से 2019 के बीच 63 लाख नये मतदाता जुड़े जबकि 2009 से 2014 के बीच 75 लाख तथा 2004 से 2009 के बीच एक करोड़ नये मतदाता बने थे।

अब इससे तुलना करिए। क्या लगता है कि 2024 में ऐसा असामान्य हो गया या बोगस मतदाता आ गए जैसा राहुल बता रहे हैं? लोक सभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता वृद्धि का आंकड़ा भी यही बताता है। 2024 विधानसभा में लोक सभा की तुलना में 5% अधिक मतदाता थे तो 2009 में 4%, 2014 में 3%, 2019 में एक प्रतिशत और 2024 में 4% अधिक मतदाता थे। इसलिए यह कहना कि 2024 महाराष्ट्र चुनाव में असामान्य हो गया तथ्यों के आधार पर हास्यास्पद लगता है। अंतिम घंटे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के आरोप की सच्चाई जानने के लिए प्रति घंटे मतदान का औसत निकालिए। हर घंटे औसत 5.83% मतदान हुआ। वे पूछ रहे हैं कि अंतिम एक घंटे में 7.8% की वृद्धि कैसे हो गई? 5 बजे से 6 बजे के बीच की बात करने वालों को समझना चाहिए कि जो मतदाता 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं देर होने पर भी वह मतदान करते हैं। मतदान प्रतिशत भी 5 से 6 बजे के बीच का ही अंकित होगा, किंतु हो सकता है 7 बजे 8 बजे तक मतदान हुआ हो।

यह महाराष्ट्र तक सीमित भी नहीं है। आप 2024 के लोक सभा चुनाव के कुछ आंकड़े देखिए। उदाहरण के लिए दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 60.96 था। अगले दिन आंकड़ा 66.71% आया। इस तरह वृद्धि 5.75% की थी, लेकिन महाराष्ट्र में उस चुनाव में कांग्रेस और महा विकास अगाड़ी की विजय हुई थी। राहुल और विरोधी उसका उल्लेख नहीं करते। आप स्वतंत्रता के बाद से किसी भी चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो सबमें इस तरह कुछ चुनिंदा आंकड़ों के विश्लेषण से विसंगति धांधली दिखाई पड़ेंगे। दूसरे तथ्य सामने आते ही आशंकाएं ध्वस्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में धांधली नहीं हुई। अतीत में अनेक चुनाव धांधली से जीते गए। यह सब कांग्रेस के राज में हुआ। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। इसको हर हाल में परास्त करना होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

> आप स्वतंत्रता के बाद से किसी भी चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो सबमें इस तरह कुछ चुनिंदा आंकड़ों के विश्लेषण से विसंगति धांधली दिखाई पड़ेंगे। दूसरे तथ्य सामने आते ही आशंकाएं ध्वस्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में धांधली नहीं हुई। अतीत में अनेक चुनाव धांधली से जीते गए। यह सब कांग्रेस के राज में हुआ। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। इसको हर हाल में परास्त करना होगा

टेस्ला की आमद पर बताशे बांटनेवाले न भूलें कि कभी इंग्लैंड के Charter Act 1833से अधिकृत ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के Wellesley, Hastings आदि गवर्नर जनरलों ने भी भारत में कूटनीति से कंपनी बहादुर का राज फैला कर 1856 में हिमालय से बर्मा तक को 2 सदी तक खुली लूट का अड्डा बना लिया था।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

जुमलों से हमलों तक

मोदी के 11 वर्ष | डॉ. घनश्याम बादल

वैसे तो नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2025 को 11 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ उन्होंने 9 जून 2024 को ली इसलिए उनके तीसरे कार्यकाल की सरकार की वर्षगांठ 9 जून 2025 को मनाई गई।

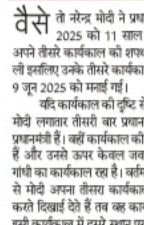

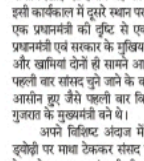

यदि कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। वहीं कार्यकाल की दृष्टि से वें तीसरे स्थान पर हैं और उनसे ऊपर केवल जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से मोदी अपना तीसरा कार्यकाल भी सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देते हैं तब वह कार्यकाल की दृष्टि से अपने इसी कार्यकाल में दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। यदि मोदी का एक प्रधानमंत्री की दृष्टि से एक विवेचन किया जाए तो प्रधानमंत्री एवं सरकार के मुखिया के रूप में उनकी खूबियां और खामियां दोनों ही सामने आती हैं। 26 मई 2014 को पहली बार सांसद चुने जाने के बाद ही वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए जैसे पहली बार विधायक चुने जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे।

अपने विशिष्ट अंदाज में उन्होंने संसद भवन की ड्योढ़ी पर माथा टेककर संसद में प्रवेश किया तो भावुक देश को बहुत आशाएं जगी थी। अपने पहले भाषण में भी मोदी ने देश को चुनाव में 'अच्छे दिनों' के वादे को पूरा करने का विश्वास दिलाया। साथ ही 'सबका साथ सबका विकास' का नारा देकर सारी राजनीतिक का कटुता भुलाकर देश के सर्वांगीण विकास की बात की और खुद को प्रधानमंत्री के बजाय 'प्रधान सेवक' की संज्ञा दी तथा कहा कि वह एक शासक नहीं बल्कि 'चौकीदार' के रूप में देश के हितों की रक्षा करेंगे। मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में निराश ही नहीं किया और एक से बढ़कर एक अभिनव योजनाएं देश के सामने रखीं, जिनमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, महिला कल्याण व स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने आम आदमी का दिल जीत लिया। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने नोटबंदी तथा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे कड़े निर्णय देकर दिखाया कि अपने संकल्प के पक्के हैं। उनकी राजनीतिक चतुराई के आगे विपक्षी पूरे कार्यकाल में एक संभ्रम की स्थिति में रहे और राहुल गांधी

को तो उन्होंने इस तरह निशाने पर रखा कि वे कभी भी खुद को उनके प्रतिद्वंद्वी साबित नहीं कर पाए। और बचकाने शब्दों 'चौकीदार ही चोर है' या 'खून का सौदागर' कहकर राहुल और उनकी मां सोनिया दोनों फंसे रहे। ऐसा नहीं कि मोदी का यह कार्यकाल एकदम सफल ही रहा उसमें विपक्ष को आलोचना का भी पूरा मौका मिला। उनके 'अच्छे दिन' और 15 लाख रुपये हर भारतीय के खाते में आने की खूब मजाक बनी जिसे बाद में अमित शाह ने एक 'चुनावी जुमला' करार देकर जान छुड़ाई। उनका नोटबंदी से कालाधन व आतंकवाद नियंत्रण का पासा भी उल्टा पड़ा। 2019 में जब लोक सभा चुनाव की घोषणा की गई राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि आएंगे तो मोदी ही पर उनकी चमक और धमक दोनों कम होगी, लेकिन 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'इस बार 300 पार' का नारा खूब चला और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने ही बलबूते पर बहुमत मिला। एनडीए की 353 सीटों उसका हिस्सा 303 पर पहुंच गया जो एक बड़ी उपलब्धि थी। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी का आत्मविश्वास आसमान छूता नजर आया। धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर का शिलापूजन हो गया, नागरिकता कानून संशोधन पास हो गया, पुलवामा में हुए हमले के बाद उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का साहस दिखाया, कृषि कानून, कोविड वैक्सीन मुफ्त राशन, मोबाइल अस्पताल और ताली थाली दीप आदि ने मोदी की लोकप्रियता को और भी बढ़ाया, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में सारी व्यवस्था चरमरा गई लाखों मौत हुईं, वैक्सीन बनाने में मानकों की अनदेखी महंगी पड़ी जो आज तक संदेह पैदा करती है। कृषि कानून, पर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा बेरोजगारी व महंगाई बेकाबू हो गई दूसरे कार्यकाल में सरकार ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्षियों को घेरने और कुचलने में किया।

उन पर बड़बोलेपन का आरोप तो खैर अब तक लगता है। 2024 के चुनाव में भी मोदी 'वन मैन आर्मी' की तरह लड़े और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाजपा को सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में वापस लाने में कामयाब रहे भले ही सीटों की संख्या 303 से गिरकर केवल 240 रह गई। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह का स्टैंड उन्होंने लिया उसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पाकिस्तान को गहरी चोट और सबक दिए हैं। हालांकि एकाएक किए गए युद्ध विराम ने मोदी सरकार को को सवालों ने घेर लिया है। राजनीति बहुत सारी करवटें लेगी। यह तो समय ही बताएगा कि 75 साल के होने जा रहे मोदी आदर्शों के नाम पर संन्यास ले लेंगे या फिर कोई नया जुमला उछाल कर अपनी सर्वोच्चता बरकरार रखेंगे।

पिछले जन्मों का करम | ओशो

एक व्यर्थ की धारणा हमें सिखा दी गई है कि तुम्हें दुःखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म तुम्हें भोगना है। यह धारणा अगर मन में बैठ गई कि मैं पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा हूं, तो सुख का उपाय कहां है? इतने-इतने जन्म! कितने-कितने जन्म! चौरासी कोटि योनियां! इनमें कितने पाप किए होंगे, थोड़ा हिसाब तो लगाओ! इन सारे पापों का फल भोगना है। सुख हो कैसे सकता है! दुख स्वाभाविक मालूम होने लगेगा। ये आदमी को दुःखी रखने की ईजाद है। मैं तुमसे कहता हूं: कोई पाप नहीं किए हैं, कोई कर्म का फल नहीं भोगना है। तुम अभी जागे ही नहीं, तुम अभी हो ही नहीं, पाप क्या खाक करोगे! पाप बुद्ध कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध पाप करते नहीं। अकबर की सवारी निकलती थी और एक आदमी अपने मकान की मुंडेर पर चढ़ गया और गालियां बकने लगा। सम्राट को गालियां! तत्क्षण पकड़ लिया गया। दूसरे दिन दरबार में मौजूद किया गया। अकबर ने पूछाः तू पागल है! क्या कह रहा था? क्यों कह रहा था? उसने कहा मुझे क्षमा करें, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने शराब पी ली थी। मैं बेहोश था। मैं था ही नहीं! अगर आप मुझे दंड देंगे, तो ठीक नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। मैं शराब पीए था। अकबर ने सोचा और उसने कहाः यह बात ठीक है; दोष शराब का था, दोष तेरा नहीं था। तू जा सकता है। मगर अब शराब मत पीना। शराब पीने का दोष तेरा था। शराब पीने के बाद जो कुछ तेरे मुंह से निकला, उसमें तेरा हाथ नहीं, यह बात सच है। आज भी अदालत पागल आदमी को छोड़ देती है, अगर पागल सिद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि पागल आदमी का क्या दायित्व? किसी पागल ने किसी को गोली मार दी। अदालत क्षमा कर देती है, अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है। क्योंकि पागल आदमी को क्या दोष देना, उसे होश ही नहीं है! तुम होश में रहे हो? ये जो चौरासी कोटि योनियां जिनके संबंध में तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, तुम होश में थे? तुम्हें एकाध की भी याद है? अगर तुम होश में थे, तो याद कहां है? तुम्हें एक बार भी तो याद नहीं आती कि तुम कभी वृक्ष थे, कि तुम कभी एक पक्षी थे, कि तुम कभी जंगल के सिंह थे। तुम्हें याद आती है कुछ? शास्त्र कहते हैं; तुम्हें याद नहीं। और तुम गुजरे हो चौरासी कोटि योनियों से। तुम बेहोश थे, तुम मूर्च्छित थे। मूर्च्छा में जो भी किया गया, उसका क्या मूल्य है? परमात्मा अन्याय नहीं कर सकता।

रीडर्स मेल

निजता का अधिकार जरूरी

हर नागरिक को निजता का अधिकार है, इसलिए आम लोगों का डाटा संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है। आज के दौर में डाटा सुरक्षा एक अनिवार्य मुद्दा बन गया है। हमारे दैनिक दिनचर्या में साइबर स्पेस का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक ओर साइबर पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर डाटा संरक्षण के अभाव में साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सरकार को स्वदेशी डिजिटल मंच विकसित करना चाहिए। कई बार बच्चों की लापरवाही से डाटा की चोरी हो जाती है। देश में बच्चों द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सरकार को डाटा संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

रायशुमारी से बनेगी बात

'ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी' इटली में एक राष्ट्रीय-रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लोकलुभावन राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में देश की सत्तारूढ़ पार्टी है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी कर रही हैं। बीते रविवार को इटली में रायशुमारी का पहला दौर कराया गया, जिसमें लोगों को आप्रवासन को लेकर कुछ बदलाव पर अपनी सहमति देनी है। पहला प्रस्ताव गैर-ईयू निवासियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा अवधि को 10 वर्ष से घटाकर केवल पांच वर्ष करने का है, जिससे इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के बराबर हो जाएगा। अभियानकर्ताओं का तर्क है कि इस बदलाव से लगभग 2.5 मिलियन लोगों को लाभ हो सकता है और केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। लाखों अप्रवासियों का भाग्य दांव पर है क्योंकि इटली के लोग दो दिवसीय जनमत संग्रह में मतदान में भाग ले रहे हैं, जिसमें कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है। जनमत संग्रह में बेहतर नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम सुधारों को वापस लेने की भी मांग की गई है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत में आता तो इसे सरकार मेज थपथपा के लागू करवा देती।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

विकास की बयार सभी तक

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पुल का उद्घाटन कर दिया है। कह सकते हैं कि अब कश्मीर की वादियों से निकल कर ताजगी भरा सेब, चेरी, कैसर और अन्य ड्राई फ्रूट्स कुछ ही घंटे में दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा तो कश्मीरी सेब की मिठास को रफ्तार मिल सकेगी। क्योंकि पहले देश के बड़े शहरों में कई दिनों में पहुंचता था अब वह कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। अतः इसे हम एक प्रसन्नता की कह सकते हैं कि विश्व के इस सबसे ऊंचे पुल के जरिए जो चिनाब नदी पर बना है के दम पर रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश जुड़ जाएगा। हमेशा से एक दर्द सालता रहता था कि कश्मीर में रेलवे लाइन न होने से पर्यटकों को काफी परेशानियां आती थी। बस से यात्रा करने में ज्यादा समय लगता था, पर अब यहां रेलवे लाइन आ जाने से इधर का आवागमन अवश्य सुगम एवं सरल बना जाएगा एवं पर्यटन को भी बल मिल सकेगा।

मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

वर्ष-34, अंक 294

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बाराखंबा लेन, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रूनेश मिश्र* ।

दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 10 जून 2025

हुनर पर करिए गौर

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जन्मदर बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फाइनैंशल इन्सेंटिव्स देने की योजना बनाई है। चंद्रबाबू के इस फैसले के पीछे सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक कारण हैं।

विरोधी विचार । नायडू का कहना है कि परिवार जितना बड़ा होगा, उसे उतना ही ज्यादा आर्थिक अनुदान मिलेगा। विडंबना है कि इसी आंध्र प्रदेश में ऐसे लोगों को निकाय चुनावों में खड़े होने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं।

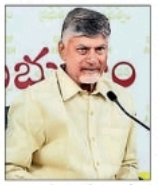

आबादी बढ़ाने पर जोर

सीटों की चिंता । दरअसल, आंध्र समेत दक्षिण के सभी राज्यों में यह चिंता है कि कम आबादी की वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत में कमी आई है। परिसीमन पर दक्षिण का विरोध इसी वजह से है कि उत्तर के राज्यों की तुलना में उनके यहां लोकसभा की सीटें कम बढ़ सकती हैं और इससे देश की सियासत में वह कमजोर पड़ जाएगा। चंद्रबाबू इसी के चलते दक्षिणी राज्यों से अपनी जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं।

चीन का उदाहरण । हालांकि जनसंख्या इस तरह स्टॉप-स्टार्ट मोड में काम नहीं करती और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। पेइचिंग ने करीब चार दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी का सख्ती से पालन किया। जब इसका असर उसकी वर्कफोर्स पर पड़ा, तो 2015 में उसने पॉलिसी बदलते हुए दो बच्चों और फिर तीन बच्चों तक की छूट दे दी, लेकिन इससे उसकी जन्मदर पर खास फर्क नहीं पड़ा। वजह है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही लोगों का ध्यान क्वॉलिटी लाइफस्टाइल की तरफ गया है।

जन्म दर में गिरावट । दक्षिण का यह डर कि उसकी आबादी गिर रही है, वास्तव में तस्वीर को आधुरा देखना है। असल में पूरे देश में जन्म दर में गिरावट आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि देश में फर्टिलिटी रेट (TFR) 2.0 है यानी हर कपल औसतन दो बच्चे पैदा कर रहा है। सबसे कम, 1.4 TFR दिल्ली और पश्चिम बंगाल का था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फर्टिलिटी रेट 1.5, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में 1.6 दर्ज किया गया था।

असल लक्ष्य । शिक्षा के साथ आई जागरूकता के कारण पिछले दशक से आबादी में बढ़ोत्तरी नियंत्रण में आई है। भारत के सामने समस्या जनसंख्या घटने की नहीं, बल्कि यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह स्किल्ड बनाया जाए ताकि वे भी विकास में साझीदार हों और उनके जीवन स्तर में सुधार आए।

धूप-छांव

दो-चार पल एक्स्ट्रा!

प्रणव प्रियदर्शी

'सो, हाउ आर यू मि. हैपिली मैरिड मैन?' एक जाने-माने फिल्ममेकर अपने एक स्क्रिप्ट राइटर से मुखातिब थे। करीब ढाई दशक पहले हुई इस बातचीत में आया संबोधन - मिस्टर हैपिली मैरिड मैन – तारीफ से ज्यादा व्यंग्य का पुट लिए हुए था। वजह यह थी कि एक दिन पहले ही युवा स्क्रिप्ट राइटर फिल्म यूनिट के लोगों के लिए दी गई पार्टी बीच में ही छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना था। अपनी हल्की-फुल्की टिप्पणी के जरिए फिल्ममेकर ने उस स्क्रिप्ट राइटर को इंडस्ट्री के वर्क कल्चर की तमीज सिखाने की कोशिश की, इस रूप में कि यहां पार्टी भी काम का ही हिस्सा होती है और काम से जी चुराते हुए दिखना ठीक नहीं।

यह अलग बात है कि उस युवा स्क्रिप्ट राइटर पर तब उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ उसके व्यक्तित्व की बनावट कहिए और कुछ उम्र की खासियत, ऐसी हर बात उसके सामने असरहीन साबित होती थी जो उसे अपने घर और परिवार की खुशियों से दूर ले जाती दिखती हो। मुंबई के किसी सुदूर उपनगर में बढ़िया आरामदायक घर खरीद लेने की सलाह भी ऐसी ही एक बात थी। वरसोवा जैसे अपेक्षाकृत महंगे इलाके में किराये पर फ्लैट लेकर रहना उसे ज्यादा समझदारी वाला फैसला लगता था क्योंकि इससे पैसा नहीं, पर समय भरपूर बचता था। उसने कहा, 'सब कहते हैं 25 साल की EMI के बाद वह घर तुम्हारा हो जाएगा, जबकि यहां हर महीने चुकाया जाने वाला किराया पानी में जा रहा है। लेकिन यार, यहां रोज तीन-चार घंटे टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे परिवार के साथ। यह वक्त मुझे अभी चाहिए, 25 साल बाद नहीं। मेरे बच्चे तो रोज-रोज बड़े हो रहे हैं ना। कुछ साल बाद वे फिर से तो बड़े नहीं होंगे।'

यही सवाल उस पार्टी से जल्दी घर ले गया था, जिससे वह अपने तत्कालीन बॉस फिल्ममेकर के निशाने पर आया था। और, यही सवाल आजकल फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण और इंडस्ट्री की कुछ बड़ी हस्तियों के बीच चल रही रस्साकशी के भी केंद्र में है। आठ घंटे की शिफ्ट का आग्रह नया नहीं है। दीपिका जैसी नई मांओं का एंगल इस तरफ भी ध्यान खींच रहा है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जिन लोगों की मेहनत पर इंडस्ट्री की चमक-दमक बरकरार है, कुछ ध्यान उनके जीवन की गरिमा बनाए रखने पर भी देना क्या इतना मुश्किल है?

बोल वचन

उतार दें भद्रा?

राहुल पाण्डेय

बचपन में हम बच्चे जब शरारत करते-करते अति कर दें, तो अम्मा उठाएं चप्पल और बोलें, आज तुम लोगों का भद्रा ना उतार दिया तो कहना। तब भद्रा का मतलब हमें यही समझ में आता था कि यह सिर पर चढ़ी शैतानी है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को एक अशुभ योग माना जाता है। अंगिका में यह द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों की संज्ञा होती है। अवधी में भद्रा विघ्न-बाधा भी है तो एक अपमानजनक बात भी। केकयराज की एक कन्या भगवान कृष्ण से ब्याही थीं, उनका नाम भी भद्रा था। भद्रा छाया के गर्भ से पैदा हुई सूर्य की भी कन्या हैं। शमी का वृक्ष, जिसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, उसे भी भद्रा कहते हैं। गढ़वाली में नखरे करने वाली को भद्रा कहते हैं तो ब्रज में हल्दी, दूध, कटहल, गाय और धरती को भी भद्रा कहते हैं। अवध से लेकर मगध तक जिस भद्रा को सबसे पहले एक अशुभ योग माना जाता है, वह ब्रज आकर कल्याण करने वाली एक शक्ति में भी बदल जाती है। महात्मा बुद्ध की एक खास शक्ति भी भद्रा कहलाती है। मैथिली में भादों में काटे जाने वाले धान को भी भद्रा या भदरा कहते हैं। जाहिर है, भद्रा के इतने सारे अर्थों को किसी एक शब्द में पिरोने में अंग्रेजी क्या, किसी भी भाषा का भद्रा उतर जाएगा।

AI Image

RCB के सम्मान समारोह में हुई त्रासदी से सबक़ लेने और सभी की ज़िम्मेदारी तय करने की ज़रूरत

कैसे रोका जा सकता था RCB हादसा

अशोक कुमार

हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सम्मान समारोह के दौरान हुई त्रासदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में क्राउड मैनेजमेंट में लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।

जश्न की जल्दी । भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसका पूर्वानुमान लगाना, सटीक रणनीति और सभी पक्षों के साथ तालमेल रखते हुए कार्ययोजना को दुरुस्त से लागू करना जरूरी है। परंपरागत रूप से धार्मिक आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक रैलियों, सिलेब्रिटी प्रोग्राम और प्रमुख खेल आयोजनों - खासकर क्रिकेट में भी ऐसी भीड़ जुटानी शुरू कर दी है, जहां अक्सर क्राउड मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं किया जाता। भीड़ का व्यवहार बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि मौके पर स्थितियां कैसी हैं। भीड़ का व्यवहार असंयमित और अनुशासनहीन होता जा रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि RCB ने जश्न मनाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखाई।

पुलिस पर दबाव । यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बेंगलुरु पुलिस ने इस आयोजन के लिए अनुमति दी थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं दी गई थी, तो क्या आयोजकों को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई थी। कुछ खबरों के अनुसार, राज्य सरकार ने पुलिस की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए 3 जून को ही समारोह की मंजूरी दे दी थी। यह भी पता चला रहा है कि पुलिस ने इसका विरोध किया था। ऐसे मौकों पर यह कड़वी सच्चाई सामने आती है कि राजनीतिक और जनता के दबाव में आज पुलिस अपने निर्णय लागू नहीं कर पाती। उसकी पहले से सीमित शक्ति को और कमजोर किया जा रहा है।

असंवेदनशील व्यवहार । इस मामले में RCB मैनेजमेंट, DNA (आयोजक) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) का रवैया असंवेदनशील और अहंकारी लगा। पुलिस की चेतावनी के बाद भी उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा। सबसे अधिक हैरानी की बात तो यह रही कि हादसे के बाद भी कार्यक्रम रोका नहीं गया। मृत्यु एंट्री की घोषणा ने हालात और बिगाड़ दिए। अगर सीमित संख्या में ऑनलाइन पास 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिए जाते, तो हालात संभाले जा सकते थे।

नेताओं की मौजूदगी। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस को बलि का बकरा बनाया गया। जब राज्य के बड़े नेता किसी आयोजन में शामिल होते हैं, तो पुलिस के लिए उस कार्यक्रम को रोकना या मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी ने सम्मान समारोह को एक तरह से आधिकारिक मान्यता दे दी। इससे पुलिस की चेतावनी बेअसर हो गई।

अनुमान में चूक । आयोजकों और प्रशासन ने कार्यक्रम से पहले जोखिम का पूर्वानुमान नहीं लगाया। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एनालिटिक्स और जमीनी जानकारी के जरिए संभावित भीड़ का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ होता तो जनता को सचेत किया जा सकता था कि भारी संख्या में न आएं। सीमित संख्या में ऑनलाइन पास देकर, एंट्री पर नियंत्रण रखकर और बैठने की पक्की व्यवस्था करके भीड़ को संभाला जा सकता था। बैरीकेडिंग, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के जरिये भी क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकता था।

यह करना चाहिए था । मान लीजिए कि पहले के सारे अनुमान गलत साबित हुए, तो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग से हालात को संभाला जा सकता था। जब स्थिति खतरनाक हो रही थी, तब सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से मेसेज दे सकते थे कि और लोग न आएं। स्टेडियम के बाहर, तीन-चार किमी के दायरे में इमरजेंसी बैरीकेडिंग की जा सकती थी, भीड़ को बड़े इलाके में फैलाया जा सकता था।

त्रासदी के सबक । भावनाओं और श्रेय लूटने की होड़ को सुरक्षा और समझदारी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भीड़ को संभालना राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि खास जिम्मेदारी वाला काम है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, खतरे वाले इलाकों की पहचान, अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल, सख्त नियम और सबसे जरूरी - राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होती है।

सभी की जवाबदेही । पुलिस की चेतावनियों को गंभीरता से लेना जरूरी है - आखिरकार वही मैदान पर खतरनाक हालात का सामना करती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाना और उसे सख्ती से लागू करना अब जरूरी कदम बन गया है। साथ ही, बिना जांच के पुलिस पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं। जवाबदेही सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब तक आयोजकों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक, सभी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसे जश्न हादसों में बदलते रहेंगे।

(लेखक उत्तराखंड के पूर्व DGP और खेल विश्वविद्यालय के VC हैं)

हादसे की वजह

- बेंगलुरु पुलिस की चेतावनियों को अनदेखा किया गया
- समारोह में शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से व्यवस्था बिगड़ी
- भीड़ के पूर्वानुमान और लगातार मॉनिटरिंग में भी हुई चूक

छोटे साब कहिन, दिल्ली चलो या अंटार्कटिका

आलोक सिंह भदौरिया

दिल्ली, गोरखपुर या अंटार्कटिका- अब सोच लीजिए समर वेकेशन में कहां जाना है?... आज दोपहर तक जिंदगी सुकून से कट रही थी। मई निकल चुका था, जून का पहला हफ्ता चल रहा था। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां बस कुछ दिनों की मेहमान थीं। लेकिन सामने वाले पड़ोसी अपने घर की चाबियां थमाते हुए बोले, भइया हम उत्तराखंड जा रहे हैं जरा सुबह-शाम पौधों में पानी डालते रहिएगा।

हमने झट से चाबी उनके हाथ से ली ताकि हमारे सपूत जी यह सब देख-सुन न लें। लेकिन अफसोस देर हो चुकी थी। बेटा जी अपने दोस्तों को बाय करने ऑटो तक निकल चुके थे। हमें वैसा ही लगा जैसे 'बनारसी साड़ियों की सेल... 50 पर्सेंट छूट' का विज्ञापन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी पत्नी जी के कर कमलों तक पहुंच जाए।

खैर... बेटा जी मुंह फुलाए वापस आए। मुंह खोलने से पहले दोनों आंखों से 8-8 आंसू टपकाए और बोले, सब घूमने जा रहे हैं। हम कहीं नहीं गए। समर वेकेशन भी खत्म हो रही है। हमने बहानों की पूरी स्क्रिप्ट मन ही मन दोहराई। उसे बताया कि इस समय गर्मी बेतहाशा है, नौतपा चल रहा है, ऊधर कोरोना अलग बेताब हो रहा है। ऐसे में पागल ही हैं जो बाहर घूमने की सोच रहे हैं।

जवाब में आर्यपुत्र ने मोहल्ले के कम से कम 15 और अपनी डांस क्लास के 5 ऐसे उदाहरण हमारी शान में पेश कर दिए, जो मनाली से लेकर मुंबई तक और शिमला से लेकर स्विट्जरलैंड तक समर वेकेशन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। हमारे चश्मेचिराग का तर्क था कि 1 जुलाई को जब उनकी मैम पूछेंगी कि समर वेकेशन में कौन कहां-कहां गया, तब क्या जवाब दिया जाएगा।

हमने साम, दाम, दंड, भेद सभी हुनर आजमाए, और इस कदर आजमाए कि एक बार को हमारे सपूत की माता जी भी झांसे में आ गईं लेकिन कक्षा 1 का यह नौनिहाल अंगद का पैर बन चुका था। लिहाजा हमने कुटिल चाल चलते हुए कहा कि चलो नानी घर चलते हैं। इरादा था कि माता-पुत्र दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार.... पर यह सुनने के बाद 4 फुट का वह बंदा करीब 6 फुट उछल गया। बोला, कतई नहीं, नानी घर जा-जाकर बोर हो गया हूं, नाना ना मैगी खाने देते हैं ना कार्टून देखने देते हैं।

हमने हथियार डालते हुए पूछा अब बताओ कहां जाना है, तब भाई ने दिल्ली, गोरखपुर और अंटार्कटिका का ऑप्शन दिया। अंटार्कटिका इसलिए क्योंकि उनका फेवरिट कार्टून कैरेक्टर अंटार्कटिका की बर्फ में स्नोमैन बना रहा है। हमने अर्जी लगाते हुए कहा, गोरखपुर तो रक्षाबंधन पर जाएंगे, दिल्ली ट्राई कर सकते हैं अगर रिजर्वेशन मिला तो। लेकिन अंटार्कटिका हमारी औकात और बूते के बाहर है।

अब पिछले एक घंटे से IRCTC की साइट खंगाल रहे हैं। किसी ट्रेन में ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है जो समर वेकेशन खत्म होने से पहले हमें दिल्ली ले जाए। टिकट का रेट भी ऐसा कि हमें पहले तो शक हुआ कि कहीं रेलवे हवाई जहाज तो नहीं चलाने लगा।

हालत यह है कि अगर हमें जल्द ही दिल्ली की टिकट न मिली तो किसी ट्रैवेल एजेंट से कहकर अंटार्कटिका का पैकेज पूछना पड़ेगा, फिर जो कुछ माल-ओ-अस्बाब है उसे गिरवी रखकर टिकट का बंदोबस्त करना होगा। आखिर छोटे साब की इज्जत का सवाल है, उन्हें अपनी मैम और बिलांद भर के दोस्तों पर रौब भी तो गांठना है।

AI Image

ऐवें कुछ भी

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

छिपी ताक़त बाहर लाने का अवसर देती हैं मुश्किलें

देवेंद्रराज सुथार

जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब सब कुछ जैसे ध्वस्त होता प्रतीत होता है। कोई कार्य हमारी आशाओं के अनुसार नहीं होता, संबंध टूट जाते हैं, स्वास्थ्य या करियर में ऐसी बाधा आती है, जिससे हम टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है जब हमने पूर्ण निष्ठा और प्रयास के साथ कार्य किया हो, फिर भी परिणाम हमारे विरुद्ध गया हो। लेकिन, समय बीतने पर जब हम उस क्षण को फिर स्मरण करते हैं, तो पाते हैं कि वही घटना, जिसने हमें तोड़ा था, हमारे भीतर एक नई संरचना की नींव रख गई।

राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती को निमंत्रण के बावजूद यज्ञ में तिरस्कार सहना पड़ा। सती ने अपने पिता के प्रति विरोध स्वरूप अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के पश्चात भगवान शिव अत्यंत व्यथित हुए, उन्होंने सती के मृत शरीर को लेकर तांडव किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंड-खंड कर गिराया, जिससे शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। धार्मिक दृष्टि से यह घटना विनाश का प्रतीक हो सकती है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से यह धार्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है - जहां अहंकार (दक्ष) का पतन हुआ, शक्ति की पुनर्स्थापना हुई और हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शक्ति (सती) का पुनर्जन्म हुआ। यह चक्र बताता है कि नाश के बाद नवनिर्माण भी निश्चित है।

बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है, तो वह अंकुरण के पहले अंधकार में रहता है। यह अंधकार उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि विकास का वातावरण है। महान चित्रकार Vincent van Gogh ने अपने जीवन में अनेक अस्वीकृतियां झेलीं। मानसिक अस्थिरता और सामाजिक तिरस्कार के बाद ही उन्होंने अपनी सबसे अनोखी कृतियां रचीं, जैसे 'The Starry Night', जो आज विश्व प्रसिद्ध है। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूती का पाठ पढ़ाती है। मुश्किलें जब हमारे सामने आती हैं, तब वे हमारी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने का अवसर देती हैं। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें न केवल उबारती है, बल्कि बेहतर इंसान भी बनाती है।

कई बार हम जिसे 'समस्या' कहते हैं, वह दरअसल 'संकेत' होती है कि अब बदलो, अब बढ़ो, अब अपनी जड़ता को छोड़ दो। दुनिया की सबसे शांत और गहरी झीलों को भी पहले उथल-पुथल से गुजरना पड़ता है। ईसांत भी ऐसा ही है - जितना भीतर खंगाला जाएगा, उतना चमकेगा। सही मायनों में, जीवन की पूर्णता यह नहीं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बना लें।

नौकरी की इच्छा से जर्मनी आने वाले भारतीयों के लिए यह बहुत सही मौक़ा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले दिनों जर्मनी का दौरा किया। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने और वहां नई सरकार बनने के बाद यह दौरा अहम रहा। द्विपक्षीय संबंधों के तार शिक्षा, मोबिलिटी और माइग्रेशन से भी जुड़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर दिल्ली में जर्मनी के एंबेसडर **डॉ. फिलिप एकरमैन** से NBT की **अल्पयु सिंह** ने बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश :

■ विदेश मंत्री एस. जयशंकर हाल ही में जर्मनी में थे। द्विपक्षीय संबंधों को पर आगे की राह कैसी है?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस दौरे ने द्विपक्षीय संबंधों के तहत जर्मनी की नई सरकार का वह रुख दिखा दिया, जिसके तहत दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जर्मनी में जो सरकार थी, उसका भी भारत को लेकर ऐसा ही नजरिया था। भारत इस क्षेत्र में जर्मनी के अहम रणनीतिक साझेदारों में है। हम उस पर फोकस जारी रखेंगे। भारत हमारी विदेश नीति के केंद्र में रहेगा।

■ भारत-EU FTA वार्ता अब जोर पकड़ रही है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंधों को लेकर आगे की दिशा कैसी रहेगी?

मुझे विश्वास है कि इस साल के आखिर तक EU-भारत की FTA को लेकर वार्ताओं में बेहतरीन प्रगति होगी। भारत की विदेश नीति में EU बहुत अहम स्थान रखता है। ऐसे ही EU के बारे में कहा जा सकता है कि भारत भी उसकी प्राथमिकताओं में है। इसी साल फरवरी में 21 कमिश्नरों के साथ EU आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर की भारत यात्रा शानदार थी। मुझे लगता है कि उनकी इस यात्रा से EU और भारत के बीच भविष्य में संबंधों की एक दिशा तय होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन संबंधों के केंद्र में रहेगा।

■ आप कहते रहे हैं कि जर्मनी चाहता है, ज्यादा भारतीय प्रफेशनल्स आपके देश आएं। दोनों देश मिलकर मोबिलिटी बढ़ाने पर किस तरह का सहयोग कर रहे हैं?

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

जर्मनी को इस वक्त स्किल्ड लेबर की जरूरत है। सरकार ने हाल ही में एक उदार इमिग्रेशन बिल पास किया है, जो कि भारत से प्रफेशनल्स को जर्मनी आकर नौकरी ढूंढने की इजाजत देता है। IT, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में प्रफेशनल्स की जरूरत है। अगर भारतीय इन क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं, तो उनके लिए सही वक्त और माहौल है। जहां तक छात्रों की बात है तो फिलहाल जर्मनी में 50 हजार भारतीय छात्र पहले से हैं। दुर्भाग्य से हमने एक पैटर्न देखा है कि एजेंसियों के बहकावे में आकर ये छात्र प्राइवेट कॉलेजों का रुख करते हैं, जो ना सिर्फ बहुत महंगे हैं, बल्कि ये इन्हें जर्मन डिप्लोमा या डिग्री भी नहीं देते। उदाहरण के तौर पर, ऐसे निजी संस्थान छात्रों को ब्रिटेन, इटली या पोलैंड का डिप्लोमा देते हैं, क्योंकि ये असल में जर्मन विश्वविद्यालय है ही नहीं। छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि इन संस्थानों में उन्हें शिक्षा का वह उच्च स्तर हासिल नहीं होगा, जो कि जर्मनी के सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलेगा, जो ज्यादा किफायती भी हैं।

■ बीते दिनों ऐसी खबरें आईं कि यूरोप के कुछ देशों में भारतीय छात्रों और प्रफेशनल्स को भारी और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी दिक्कतें हुईं। जर्मनी इस मामले में अलग क्यों और कैसे है?

ग्रैजुएशन के बाद जर्मनी में प्रफेशनल काम या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश जरूर करनी पड़ती है। लेकिन ग्रैजुएशन के बाद छात्रों को काम ढूंढने के लिए 18 महीने का वीजा मिलता है। जर्मन सीखने से रोजगार के कई नए रास्ते खुल जाते हैं। आमतौर पर जर्मनी में अंग्रेजी काफी बोली जाती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इंग्लिश बहुत आम नहीं है। यह एक चुनौती हो सकती है। ऐसे में जो भी लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, बेहतर होगा कि वे जर्मन सीखने की सोचें। मैं भारत में अभी भी हिंदी पर काम कर रहा हूं। हिंदी सीखने के अपने शुरुआती दौर में होने के बावजूद, इस कमाल की भाषा से नजदीकी ने मेरे यहां के अनुभव को बहुत समृद्ध किया है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ भारत के लिए मौका

9 जून को छपा संपादकीय 'देर आए, दुरुस्त आए' पढ़ा। आखिरकार भारत को कनाडा में होने वाली G7 बैठक का न्योता मिल ही गया। शायद आंतरिक राजनीतिक दबाव के चलते कनाडा इस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक नहीं था। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि भारत हर विवाद को बातचीत से सुलझाने का पक्षधर रहा है। निश्चित तौर पर यह निमंत्रण भारत और कनाडा में द्विपक्षीय बातचीत के नए द्वार खोलेगा। इससे दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने और कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थकों पर लगाम कसने में मदद मिल सकती है। यही नहीं, भारत को G7 देशों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाक प्रायोजित आतंकवाद और ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर चर्चा करके अपना पक्ष स्पष्ट करने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा।

बृजेश माथुर, ईमेल से

■ शुरुआती कदम

यह पत्र 7 जून के लेख 'लेकिन कुल गुरु भी तो पुरुष है' से संबंधित है। एनबीटी की ओर से चलाई गई बराबरी की भाषा मुहिम सराहनीय है। JNU ने अब डिग्री और प्रमाण पत्रों पर 'कुलपति' शब्द हटाकर 'कुलगुरु' लिखने का फैसला किया है। इसे भाषा में लैंगिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखने की एक अच्छी शुरुआती पहल कहा जा सकता है। लेकिन यह काफी नहीं। गौर करने की बात है कि 'गुरु' कोई लिंगनिरपेक्ष शब्द नहीं है। जाहिर है, जेएनयू को इसके लिए ऐसा कोई शब्द तय करना चाहिए जो बराबरी की भाषा के दायरे में आ सके।

मीना धानिया, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ भेज करें।

अंतिम पत्र

चिराग बोले, बिहार के लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा - एक खबर

– लेकिन नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ेगी, उसका क्या!

धर्मेंद्र सिंह

12 प्रतिशत हिस्सेदारी बांग्लादेश की है, भारत से किए जाने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के निर्यात में। वर्ष 2024 में भारत ने बांग्लादेश को 11.06 अरब डालर का निर्यात किया था।

दक्षिण एशिया

जयप्रकाश रंजन
jpranjan@del.jagran.com

भारत के लिए फिर से बढ़ रही चुनौती

भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के बाद वैश्विक स्तर पर कई देशों ने चिंता जताई है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य तनाव के अलावा भी दक्षिण एशिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत के हितों के अनुरूप होता नहीं दिख रहा है। वस्तुतः बांग्लादेश और म्यांमार में जिस तरह से अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वह भारत के लिए सही नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान के साथ बढ़ता गठजोड़ भी भारत के लिए चिंता का विषय है

बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नजर गड़ी है जिसे वह अपने सैन्य अड्डे के रूप में विकसित करना चाहता है। फाइल

पहलगाम हमला और उसके बाद भारत के आपरेशन सिंदूर की वजह से दक्षिण एशिया हाल के दिनों में दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में रहा है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, अफ्रीकी महादेश व दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर यूरोपीय देशों व एशिया के अन्य देशों ने भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव की मौजूदा स्थिति के अलावा भी दक्षिण एशिया में बहुत कुछ हो रहा है। असलियत में देखा जाए तो जिस तरह से वैश्विक शक्तियां इस समूचे क्षेत्र में सक्रियता दिखा रही हैं, वैसी स्थिति केवल पिछली सदी के सातवें दशक में ही दिखाई दी थी। तब अमेरिका और रूस के बीच प्रतिस्पर्द्धा का असर दक्षिण एशिया में दिखाई दिया था और अब रूस की जगह चीन ले चुका है। अमेरिका और चीन के बीच अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में शतरंज की बिसात बिछती दिख रही है। अभी गेम की शुरुआत ही है और इसका रुख किस तरफ होगा, यह तो साफ नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि जो भी परिणाम होगा उसका भारत पर बड़ा असर होगा।

पिछले दिनों एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों का आदान-प्रदान हो रहा था, तभी भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के आर्थिक हितों के खिलाफ कदम उठा रहे थे। पहले बांग्लादेश ने जमीनी रास्ते से भारतीय सूत का आयात करना बंद किया तो उसके बाद भारत ने बांग्लादेश में तैयार रेडीमेड गार्मेंट्स का जमीनी रास्ते से भारत व यहां से दूसरे देशों को होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। इस खबर के बीच यह बात कहीं दब कर रह गई कि लंबे अरसे बाद बांग्लादेश और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने लगा है। बांग्लादेश के काक्स बाजार में अमेरिकी सेना और वायु सेना के सदस्यों के साथ बांग्लादेश की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास चल रहा है। वैसे यह अभ्यास असैनिक महत्व का है, लेकिन इसके मायने गहरे हैं। इसके तार कहीं न कहीं म्यांमार की मौजूदा आंतरिक हालात से जुड़े हैं। म्यांमार में सैनिक शासक कमजोर पड रहे हैं और देश के कई इलाके में विद्रोही समूहों का कब्जा हो चुका है। अमेरिका इन विद्रोही समूहों को शह देने की योजना बना रहा है। ऐसा करके वह सैनिक शासक व प्रधानमंत्री मिन आंग ह्लाइंग के लिए हालात मुश्किल करना चाहता है, लेकिन असली निशाने पर चीन है जो सैनिक तानाशाह को लगातार प्रश्रय दे रहा है।

अमेरिका का दोहरा रवैया : म्यांमार में अमेरिका के बढ़ती रुचि को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से म्यांमार के रखाइन प्रांत के लिए मानवीय आधार पर गलियारा बनाने के प्रस्ताव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। इस गलियारे को बनाने के लिए अमेरिका को बांग्लादेश की मदद चाहिए। कहा तो यह जा रहा है कि इस गलियारे से रखाइन प्रांत में मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकेगी, रोहिंग्याओं का पुनर्वास किया जा सकेगा आदि। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना का कहना है कि इतना बड़ा फैसला लोकतांत्रिक सरकार को ही करना चाहिए। चीन के बढ़ते वर्चस्व से चिंतित अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपने हितों के मुताबिक विस्तार चाहता है। पूर्व पीएम शेख हसीना कह चुकी हैं कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे दिया होता तो उन्हें सत्ता नहीं गंवानी पड़ती। अभी तक जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उससे यह भी पता चलता है कि अमेरिकी सरकार की म्यांमार को लेकर तैयार इस नई नीति में भारत के साथ कोई विमर्श नहीं किया गया है। वैसे अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगने के लिए भारत को अपना अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन भारत के पड़ोस में चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए जो नीति बना रहा है, उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है।

भारत भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली वजह तो यह है कि बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक अमेरिका की बढ़ती गतिविधियां उसके दीर्घकालिक हितों के अनुरूप नहीं हैं। मोहम्मद युनुस की सरकार पहले ही भारत विरोधी रवैया अख्तियार किए हुए है। अब अगर अमेरिका म्यांमार के एक बड़े हिस्से में सैन्य विद्रोहियों की मदद करता है और उन्हें हथियार आदि उपलब्ध कराता है तो यह भारत के हितों को भी आगे कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठनों का म्यांमार के सैन्य विद्रोहियों के साथ पुराना संपर्क है। ऐसे में सैन्य विद्रोहियों को मिलने वाले गोला-बारूद, हथियार आदि पूर्वोत्तर राज्यों के अतिवादी संगठनों के हाथों में जाने का खतरा है। भारत सरकार वैसे तो चीन समर्थित सैन्य तानाशाह के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन यदि उसे सैन्य विद्रोही और सैन्य तानाशाह में चयन करने का विकल्प मिले तो वह निश्चित तौर पर मौजूदा सैन्य सरकार के साथ जाएगा।

अफगानिस्तान-चीन की निकटता : म्यांमार से सीधे अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान में विदेशी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा कोई नई बात नहीं है। पिछली सदी के सातवें दशक में रूसी सेना के आगमन से लेकर अफगानी कबीले को अमेरिकी मदद, इसमें पाकिस्तान की भूमिका सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमेरिकी सेना ने अगस्त, 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। तालिबान की सरकार फिर से वापस आई। इस बीच केवल चीन ने काबुल में लगातार अपना दूतावास चलाया है। तालिबान सरकार का अभी सबसे करीबी रिश्ता चीन से है। चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर है। अफगानिस्तान को हर तरह की मदद चीन मुहैया करा रहा है और साथ ही वहां निवेश बढ़ा रहा है। चीन की कंपनियां अफगानिस्तान का दौरा कर रही हैं। बीजिंग की वहां बेहद सक्रिय भूमिका को लेकर अमेरिका भी चिंतित है और अब उसने यह संकेत भेजना शुरू कर दिया है कि तालिबान के साथ वह संबंध विकसित करने को तैयार है। माना जा रहा है कि अमेरिका का सोच भी यही है कि अफगानिस्तान के बहुमूल्य खनिजों पर कहीं चीन का कब्जा न हो जाए जैसाकि दुनिया के कई अन्य देशों में हुआ है। अफगानिस्तान की स्थिति से भारत के हित भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लिहाजा वह अपने पारंपरिक सोच को बदलते हुए तालिबान से संबंध सुधारने में जुटा है।

दूसरी तरफ, अफगान की तालिबान सरकार का रिश्ता पाकिस्तान के साथ बहुत तल्ख है तो यहां भी चीन की तरफ से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश हो रही है। पिछले हफ्ते बीजिंग में इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियो की बैठक हो चुकी है। इसमें चीन पाकिस्तान इकोनमिक कारिडोर से अफगानिस्तान को जोड़ने की सहमति बनी है। यह बैठक भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से हुई पहली टेलीफोन वार्ता के ठीक छह दिनों बाद हुई है। साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का जिस तरह से सीधा असर दक्षिण एशिया पर पड़ता दिख रहा है, वैसा दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में इन शक्तियों की गतिविधियां उसके हितों से जुड़ी हुई हैं।

विश्व मंच पर भारत की कूटनीतिक हुंकार

नृपेंद्र अभिषेक नृप

आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त राष्ट्र की छवि गढ़ने और विश्व समुदाय को भारत के बहुलतावादी स्वरूप से अवगत कराने के उद्देश्य से हाल ही में भारत के सात प्रतिनिधिमंडलों ने 32 देशों की यात्रा की। इन प्रतिनिधियों में सांसद, पूर्व राजनयिक और विविध राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आतंकवादी संरचनाओं पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। यह पहल केवल कूटनीतिक संवाद नहीं, बल्कि भारत की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आतंकवाद के विरुद्ध उसकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरी। इन यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य पुलवामा आतंकी हमले और उसके लिए पाकिस्तान की संलिप्तता को विश्व समुदाय के समक्ष उजागर करना था। इसके साथ ही भारत ने यह भी समझाया कि कैसे उसकी प्रतिक्रिया आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध सटीक, संयमित और उद्देश्यपरक रही। भारत की ओर से यह संकेत देना आवश्यक था कि अब वह आतंकवाद के प्रति 'नया सामान्य' (न्यू नर्मल) स्वीकार कर चुका है यानी अब आतंकवाद के प्रत्युत्तर में कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं में अमेरिकी दौरा भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। यह प्रतिनिधिमंडल न्यूयार्क और वाशिंगटन गया, जहां इस बात की समीक्षा की गई कि अमेरिका में भारत की स्थिति को लेकर कैसी धारणा बन रही है। अमेरिकी पक्ष की ओर से यह संकेत मिला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम में अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि युद्धविराम उसका स्वतंत्र निर्णय था, न कि किसी मध्यस्थता का परिणाम।

वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान की ओर से भी एक समानांतर प्रयास हुआ, जिसने भारत के कूटनीतिक प्रयासों को चुनौती देने के लिए वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष रखा और प्रचार तंत्र सक्रिय किया। इन सबके बावजूद, भारत की इस कूटनीतिक पहल की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने एक संगठित, बहुलतावादी और राजनीतिक रूप से समन्वित राष्ट्र की छवि प्रस्तुत की है। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी
जुगाड़ टेक्नोलाजी

राजेंद्र कुमार सिंह

आज के दौर में जुगाड़ टेक्नोलाजी के बारे में जो जान गया, समझो जंग जीत गया। यह एक ऐसी टेक्नोलाजी है जो हर क्षेत्र में मौजूद है। कोई भी ऐसा क्षेत्र चाहे कारोबार, व्यापार या दरबार लगाने के लिए सफलता निहायत जरूरी है। विज्ञापन को आधार बनाकर रोजगार को फलीभूत करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। यही एक ऐसी टेक्नोलाजी है जिसको लगाकर अपना काम निकाल सकते हैं।

देश की राजनीति में इसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इस टेक्नोलाजी में साम, दाम, दंड, भेद के मिश्रण से जो निष्कर्ष निकलता है या जो कुछ हासिल होता है, उसी को हम आज के दौर में जुगाड़ टेक्नोलाजी के नाम से जानते हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पापड़ बेलना पड़ता है। क्योंकि इसमें भी पाने के लिए नकद नारायण की सेवा करनी पड़ती है। आप कितना भी हाथ-पांव मारिए, कुछ होने जाने वाला नहीं। यहां जो टेक्नोलाजी लागू होगी, उसे हम दूसरी भाषा में रिश्वत टेक्नोलाजी कहते हैं।

वैसे कभी-कभी लेन-देन के बावजूद टेक्नोलाजी फेल कर जाती है, क्योंकि उससे बड़ा पावरफुल जुगाड़ और जितना खर्च किए हैं उससे कोई डबल पैसा रूपी पावर उपयोग करेगा तो कम पैसा वाला उसके समक्ष धराशायी हो जाएगा।

आज हास्पिटल भी एक उद्योग के रूप में चल रहा है, जुगाड़ टेक्नोलाजी का धड़ल्ले से यहां प्रयोग हो रहा है। अस्पताल में सीट खाली नहीं है तो किसी नेता या अधिकारी का जुगाड़ लगाकर आगे बढ़े तो शायद समस्या हल हो जाए।

जुगाड़ टेक्नोलाजी के कई प्रकार हैं। पहले बात से बात बन जाए तो वार्ता टेक्नोलाजी कहते हैं। यदि सोर्स लगाने से बात नहीं बनी और पैसे का फोर्स डालकर काम निकाल सकते हैं, तो इसे रिश्वत टेक्नोलाजी कह सकते हैं। कभी डरा-धमकाकर काम निकालें तो उसे डांट-फटकार टेक्नोलाजी कह सकते हैं। आप दुनिया के किसी क्षेत्र में जाइए, इन्हें जरूर पाएंगे- अजी आप मुझसे रूठ कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा अलग-अलग रूपों में वहां हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर पाइएगा।

X पोस्ट

कनाडा द्वारा आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी को निमंत्रण भारत के वैश्विक महत्व का संकेत अधिक है, न कि भारत-कनाडा के बीच बढ़ती निकटता का। यह दोनों देशों के रिश्ते सुधरने का संकेत अवश्य है। यह भी सच है कि पश्चिम के शीर्ष साझेदार और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत को शिखर सम्मेलन से बाहर रखना कठिन है।
माइकल कुगेलमैन@MichaelKugelman

ट्रंप ने अपने रवैये से भारत सहित अमेरिका के सभी मित्र देशों को नाराज कर दिया है। ट्रंप अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं और विश्वसनीय भी नहीं है। वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें संदेह है।
डी. मुथुकृष्णन@dmuthuk

लड़का/लड़की नहीं पसंद तो मना कर दो। बच्चे मना करें तो मां-बाप भी न करें जबर्दस्ती शादी। लड़के-लड़कियों को भी चाहिए कि शादी चलाना नहीं संभव हो तो अलग हो जाएं। हत्या करके क्या मिलेगा? खुद के लिए जेल/फांसी। परिवार के लिए बदनामी। हर तरफ सिर्फ तबाही।
अशोक कुमार पांडेय@Ashok_Kashmir

जागरण जनमत
कल का परिणाम

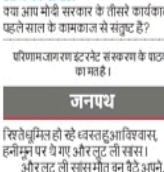

क्या आप मानते हैं कि भारत में गरीबी दर में बड़ी गिरावट का कारण मोदी सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम हैं?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आप मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल के कामकाज से संतुष्ट हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

रिश्ते धूमिल हो रहे ध्वस्त हुआ विश्वास,
हनीमून पर थे गए और लूट ली सांस।
और लूट ली सांस मीत बन बैठे अपने,
उजड़े दो परिवार सभी के टूटे सपने!
अब जीवन के मूल्य हो गए कितने सस्ते,
ले अपनों की जान खत्म होते हैं रिश्ते!!
- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

भाजपा-तृणमूल में '11' बनाम '14' की लड़ाई

बंगाल विधानसभा चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है। आगामी वर्ष की शुरुआत में ही चुनाव होना है। कहा जा सकता है कि प्रदेश में चुनाव की घंटी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं उत्तर बंगाल में जनसभा करके बता दिया कि भाजपा की चुनावी मुहिम शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता में सांगठनिक सभा कर चुनावी बिगुल भी बजा दिया। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर जिस तरह के जुबानी हमले कर रहे हैं, वह बताने को काफी है कि प्रदेश में राजनीति चुनावी मोड में आ चुकी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तृणमूल कभी विरोधी दल के नेताओं को अपने पाले में लाकर तो कभी केंद्रीय बकाया फंड के मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर है। इस बीच भाजपा और तृणमूल में '11' बनाम '14' की लड़ाई भी शुरू हो गई है।

यह लड़ाई देश में प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष के शासन बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल में 14 वर्षों के शासन को लेकर है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन 11 वर्षों में क्या-क्या किया है और किस तरह से आम जन तक फायदा पहुंचा है, इसकी रिपोर्ट लेकर नागरिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर किस तरह से प्रचार करना है, इस बारे में भाजपा नेतृत्व ने पहले ही विभिन्न स्तरों पर अपने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं तक दिशानिर्देश पहुंचा दिए थे। यह प्रचार अभियान पूरे जून जारी रहेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं को मोदी सरकार के कामकाज को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलने और मंडल स्तर पर विकसित भारत के लिए संकल्प सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया है। भाजपा सिर्फ मोदी सरकार का प्रचार ही नहीं करेगी, बल्कि

प्रतीकात्मक

लोगों को यह भी बताना शुरू कर दिया है कि बंगाल क्यों पिछड़ रहा है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता उन कारणों को भी उजागर कर रहे हैं, जिनकी वजह से केंद्र सरकार की योजना-परियोजनाएं बंगाल में लागू नहीं हो पाई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पिछले महीने के आखिर में अलीपुरद्वार की जनसभा से टोन सेट कर गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उसे विकास में विफल करार दिया था। उन्होंने इन बातों को जोर-शोर से उठाया कि बंगाल सरकार ने एक के बाद एक केंद्रीय योजनाओं को कैसे रोक रखा है और उन्हें बाधित किया है। आने वाले समय में मोदी का बंगाल दौरा बढ़ने वाला है। शाह के मामले में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि इसी माह के अंत तक मोदी फिर से बंगाल आ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा अपने नए प्रचार कार्यक्रम से कितना धमाल मचा पाती है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा की इस मुहिम के खिलाफ तृणमूल नेता और कार्यकर्ता भी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वे भी घर-घर जाकर लोगों को बताएंगे कि 14 वर्षों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार बच्चों से लेकर बुजुर्ग को मदद के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर किस तरह से उन्हें फायदा पहुंचा रही है व कैसे और लोगों को इससे जोड़ने में जुटी हुई है। यही नहीं, राम मंदिर को लेकर भाजपा की राजनीति का जवाब देने और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले हमलों से बचने के लिए ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में सागर तट पर पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर तैयार कराया है। अब रथयात्रा के मौके पर तृणमूल दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद घर-घर भेजने की तैयारी में जुटी है। प्रसाद के साथ जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर भी होगी। यह प्रसाद इस महीने तक घर-घर जाकर बांटा जाएगा। राज्य के मंत्री इंद्रनील सेन का कहना है कि प्रसाद सभी लोगों के लिए है। यह बंगाल के लिए गौरव की बात है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर मुख्यमंत्री ने ढाई साल के अंदर 20 एकड़ जमीन पर बनवाया है। भाजपा के हर प्रचार से टक्कर लेने के लिए तृणमूल ने रणनीति बना रखी है। भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे को बेअसर करने के लिए ममता साफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही हैं।

गत पांच मई को ममता सरकार ने अपने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तृणमूल की ओर से योजना बनी है कि आगामी 21 जुलाई को पार्टी के वार्षिक आयोजन शहीद दिवस रैली से ममता चुनाव अभियान का आगाज कर देंगी। इसके बाद तृणमूल नेता व कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियों और 11 वर्षों की मोदी सरकार की विफलताओं, बंगाल के साथ कथित सौतेला व्यवहार और सौ दिनी रोजगार एवं प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के फंड रोके जाने की बातें घर-घर पहुंचाने का कार्य तेज कर देंगे। तृणमूल नेताओं का विशेष जोर यह बताने पर होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता में आने के बाद से राज्य में क्या-क्या कार्य किए हैं। यह लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ने वाले चिनाब रेल ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया तो इसे लेकर भी तृणमूल हमलावर है। तृणमूल नेताओं ने पुल के निर्माण में पूर्ववर्ती सरकारों को कथित तौर पर श्रेय नहीं देने के लिए मोदी की आलोचना की। तृणमूल नेताओं ने इसी के साथ चिनाब पुल के निर्माण में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के दौरान किए गए कार्यों का भी उल्लेख कर दिया यानी वह किसी भी अच्छे कार्य का श्रेय पीएम मोदी को नहीं देने के पक्ष में है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा-तृणमूल के बीच '11' बनाम '14' की इस लड़ाई में लोग 2026 में किस पर अपना भरोसा जताते हैं।

मंथन

शुभम केवलिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

हिंदुओं-बौद्धों के बीच समरसता

बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हुआ, पर वही स्थान आज विवादों में है। ऐसे में इस मामले को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर समझा जाना चाहिए

मध्य प्रदेश के सांची में स्थित ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप। फाइल

भारत की यह पावन भूमि कई पंथों की जननी रही है। समय समय पर कई महापुरुषों ने यहां जन्म लिया, अपना दर्शन प्रतिपादित किया और आम जनमानस ने उसे अपनाया भी। महापुरुषों की यह सूची अत्यंत लंबी है जिनमें गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चार्वाक आदि प्रमुख हैं। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत की सनातन विचारधारा ने सभी पंथों को फलने-फूलने का समान अवसर दिया। सनातन वैदिक परंपरा से नए पंथों का वैचारिक मतभेद रहा, परंतु इसने कभी वैमनस्य व हिंसा को जन्म नहीं दिया।

बोधगया वह स्थान है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से मानव जाति का कल्याण हुआ, पर वही बोधगया आज विवादों में हैं। बौद्ध मतावलंबी चाहते हैं कि मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदू सदस्य न हों। इस विवाद को आधार बनाकर ही हिंदू व बौद्धों के मध्य प्राचीन समय में हुई तथाकथित हिंसा को भी हवा दी जा रही है। पर क्या हिंदू व बौद्ध धर्म में मतभेद के कोई पुरातात्विक साक्ष्य हैं?

2600 वर्ष पूर्व क्षत्रिय वर्ण में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने उस समय समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के उद्देश्य से जिस दर्शन को प्रतिपादित किया, उसे हम आज बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। हां, यह सत्य है कि बुद्ध के दर्शन में वैदिक हिंदू परंपरा में आई कुरीतियों के प्रति विरोधाभास था, परंतु इतिहास की किताबों व ग्रंथों में हिंदुओं और बौद्धों के मध्य जिस हिंसा की बात की गई, वह तो पुरातात्विक आधार पर असत्य ही प्रतीत होती है। कई इतिहासकारों ने प्राचीन ग्रंथों को आधार बताकर यह भी लिखा कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध स्तूपों का विध्वंस किया। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य हैं?

वैदिक हिंदू परंपरा : इतिहास की किताबों में जिस राजवंश को बौद्धों का सबसे बड़ा शत्रु बताया जाता है, वह है वर्तमान समय से 2200 वर्ष पूर्व का शुंग वंश। भारत के बड़े भूभाग पर शासन करने वाले शुंग राजा वैदिक परंपरा के अनुयायी थे, पर क्या शुंगों ने बौद्ध स्तूप तोड़े? उत्तर है नहीं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, वह वर्तमान समय तक केवल इसलिए सुरक्षित है, क्योंकि शुंग काल में पूरे स्तूप पर 'स्टोन केसिंग' की गई। स्तूप के चारों ओर प्रस्तर की वेदिका या प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी शुंग काल में ही करवाया गया। इतना ही नहीं, वैदिक परंपरा के ही अनुयायी सातवाहन राजाओं के काल में भी यहां चार भव्य तोरण द्वार बनवाए गए जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं अंकित हैं। यदि वैदिक हिंदू परंपरा के ये अनुयायी बौद्ध धर्म के विरोधी होते या समाज में कोई आपसी वैमनस्य होता तो क्या इस प्रकार का कार्य हो पाता, यह भी तो सोचने वाली बात है?

बौद्ध स्तूप और हिंदू मंदिर : सांची में तो बौद्ध स्तूप और हिंदू मंदिर साथ में बनाए गए हैं। स्तूप के पास ही गुप्त काल का एक मंदिर स्थित है। इसी गुप्त काल में स्तूप के प्रवेशद्वार पर महात्मा बुद्ध की भव्य प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित की गईं। ये पुरातात्विक साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं कि सनातन परंपरा के हिंदू व बौद्ध पंथों में कोई हिंसक मतभेद नहीं था। यदि हिंसक मतभेद होता तो स्तूप के भग्नावशेषों के अतिरिक्त सांची में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता।

मध्य प्रदेश का ही एक और नगर उज्जैन, यह भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। उज्जैन में भी 2300 वर्ष पूर्व एक विशाल स्तूप का निर्माण मौर्य शासकों ने करवाया था। उज्जैन शैव मत का भी एक बड़ा केंद्र है। आश्चर्य की बात यह है कि 2300 वर्ष पुराना स्तूप आज भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। यदि इतिहास की किताबों में हिंदुओं द्वारा स्तूपों को तोड़ने की बात सत्य है तो उज्जैन का विशाल स्तूप जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है, वह सुरक्षित कैसे है? हां, यह अवश्य है कि बौद्ध मतावलंबियों की संख्या में कमी आने से वैश्य टेकरी स्तूप आज एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गया है, परंतु यहां भी विध्वंस के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

बोधगया : बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बोधगया है। अशोक द्वारा सर्वप्रथम यहां मंदिर निर्माण कार्य करवाया गया था। कालांतर में इतिहासकारों द्वारा रचित बौद्ध विरोधी शुंगों ने भी निर्माण कार्य करवाए। शुंग काल में बनी प्रस्तर वेदिकाएं आज भी वहां स्थित संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। इतना ही नहीं, वैदिक परंपरा के अनुयायी गुप्त शासकों के काल में ईंटों का उपयोग करके यहां भव्य मंदिर बनवाया गया। जहां तक शशांक नामक शासक द्वारा बोधी वृक्ष तोड़ने की बात है तो यह कोरी कल्पना है। इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त वर्णित विवरणों के अतिरिक्त भी कई पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे है जो हिंदू बौद्ध हिंसा, एक दूसरे के पवित्र स्थलों को तोड़ने जैसी कपोल कल्पित बातों को निराधार सिद्ध करते हैं। हिंदू और बौद्ध सनातन परंपरा के दो अंग हैं, इनमें वैचारिक भिन्नता अवश्य है, परंतु हिंसा का न कोई स्थान था और न है।

दैनिक जागरण

तन, धन और भाग्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए

विपक्ष का कामकाज

इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को मोदी सरकार के 11 वर्षों का काम बिल्कुल भी रास नहीं आया। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले साल के कार्यकाल के कामकाज को भी खारिज करने का ही काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्था को कमजोर करने के साथ उनकी स्वतंत्रता पर हमला किया है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने 11 साल बर्बाद कर दिए और इस कालखंड में उसने संविधान के पन्नों पर केवल तानाशाही की स्याही पोती है। कांग्रेस नेता ऐसे आरोप पहले भी लगा चुके हैं। वे कुछ नया नहीं कह सके, लेकिन इस पर हैरानी है कि खरगे मोदी सरकार पर तानाशाही के रास्ते पर चलने का आरोप तब लगा रहे हैं, जब चंद दिनों बाद ही देश में आपातकाल थोपने के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर नए सिरे से पुराने आरोप लगाते समय यह भी ध्यान नहीं रखते कि उन्हें कब क्या कहना चाहिए। यह और कुछ नहीं, विरोध के लिए विरोध की राजनीति का ही परिचायक है। शायद इसी कारण दिल्ली में युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। लोकतंत्र में यह सब चलता रहता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष को सरकार की आलोचना इसी तरह करनी चाहिए? यदि किसी को इस आलोचना में सकारात्मकता अथवा रचनात्मकता दिखती है तो फिर नकारात्मकता किसे कहते हैं?

अच्छा होता कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज की गहन समीक्षा करते समय इसी अवधि में अपने कामकाज की भी परख करती और यह देखती कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के अलावा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसने क्या हासिल किया है? यह प्रश्न उसे अपने आप से करना चाहिए। ऐसा शायद ही हो, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इतने कटु संबंध नहीं होने चाहिए कि वे राजनीतिक दुश्मन जैसे दिखें। लोकतंत्र में सत्तापक्ष के साथ ही विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों को रथ के पहियों की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में अपने देश में ऐसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। विपक्ष बिना विचारे सरकार के हर फैसले का विरोध ही करने को उतावला रहता है। यह ठीक नहीं। इसका नुकसान दल विशेष को नहीं, देश को हो रहा है। उचित होगा कि सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता आपसी संपर्क और संवाद के जरिये अपने रिश्तों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह ध्यान रहे कि ताली दोनों हाथ से बजती है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में टेलीमेडिसिन सेवाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और चिकित्सकीय स्टाफ की कमी को देखते हुए सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान वर्ष 2020 में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की थी। इसके बेहतर परिणाम सामने आए। योजना के तहत स्थानीय पीएचसी व सीएचसी में आने वाले मरीजों को आनलाइन उपचार दिया जाता है। तब इस सेवा से प्रदेश के चार मेडिकल कालेजों को जोड़ा गया।

> टेलीमेडिसन सेवा के तहत पीएचसी व सीएचसी में आने वाले मरीजों को आनलाइन उपचार दिया जाता है, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं

इसका लाभ यह है कि इन मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ चिकित्सक फोन पर मरीजों से बात कर उनसे बीमारी के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी जाती है। इस सफलता को देखते हुए सरकार ने अब टेलीमेडिसिन सेवा का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अभी 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेलीमेडिसिन सेवा से जुड़े हुए हैं। अब सरकार पर्वतीय जिलों के लगभग 200 नए पीएसची को इससे जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस सेवा का सबसे ज्यादा लाभ दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले उन मरीजों को मिल रहा है, जो आर्थिक कारणों से इलाज के लिए श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून व ऋषिकेश समेत अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते। यही नहीं, आपदा व अन्य परिस्थितियों में दूरस्थ क्षेत्रों से मरीजों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उम्मीद है कि इसका गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाएगा।

अमेरिका को महान से सामान्य बनाते ट्रंप

शिवकांत शर्मा

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पैदा हुए संकट का भारत के लिए भी सबसे बड़ा सबक यह है कि वह अपने शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार का स्तर सुधारे

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 'मागा यानी फिर से महान' बनाने के लिए दो मोर्चे खोल रखे हैं। बाहरी मोर्चे पर वह अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों से टैरिफ जंग लड़ रहे हैं। भीतरी मोर्चे पर अपनी शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थाओं को वोक या वामपंथी विचारधारा के शिकंजे से मुक्त कराने की जंग लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ जंग के बिना निरंतर बेकाबू हो रहे व्यापार घाटे को कम और निर्माण उद्योग को बहाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह संस्थाओं को वोक विचारधारा से मुक्त कराए बिना दक्षिणपंथी विचारधारा को वहां जगह नहीं मिल सकती। महाशक्ति होने के बावजूद जंग के मोर्चों पर अमेरिका का रिकार्ड बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वह वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक किसी जंग में स्पष्ट जीत नहीं हासिल कर पाया। इसलिए अमेरिका के अधिकांश लोग इन दोनों मोर्चों पर अमेरिका के संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। टैरिफ जंग से होने वाले नुकसान से भी बड़ी चिंता उन शैक्षिक संस्थाओं के खिलाफ छेड़ी गई जंग को लेकर है, जिनका अमेरिका को महाशक्ति बनाने में अप्रतिम योगदान रहा है।

इसमें दो राय नहीं कि कोलंबिया, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय उत्कृष्टता एवं अनुसंधान के केंद्रों की जगह राजनीति प्रेरित विचारधाराओं का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। इसके कारण देहात और छोटे शहरों में रहने वालों का एक बड़ा वर्ग मानने लगा है कि अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्नातकों में वोक विचारधारा भर रही है। इसलिए बहाना भले ही यहूदी विरोध को समाप्त करने का हो, पर ट्रंप ने असल में अपने जनाधार को बचाने के लिए यह जंग छेड़ी है। विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि छात्रों और प्राध्यापकों के चयन की प्रक्रिया, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रमों का वैचारिक संतुलन और परिसर की गतिविधियों का विवरण साझा करें। न करने पर केंद्रीय अनुदान बंद करने, टैक्स छूट समाप्त करने और विदेशी छात्रों के वीजा रोकने-रद करने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी शर्तें मानने के बावजूद कोलंबिया विश्वविद्यालय का अनुदान रोक लिया गया। हार्वर्ड ने अपनी स्वायत्तता का हवाला देकर सरकार को अदालत में चुनौती दी। इसके बाद विदेशी छात्रों का वीजा रोकने के सरकारी आदेश को स्थगित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय और अकादमियां अमेरिका की वैज्ञानिक, आर्थिक और सामरिक शक्ति का स्रोत रही हैं। दुनिया भर से श्रेष्ठतम प्रतिभाएं पढ़ने-पढ़ाने और शोध करने यहां आती हैं। वे नई-नई खोज करती हैं, उनका कारोबार एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रयोग करती हैं और अमेरिका के विकास को गति देती हैं। विकास और शक्ति की दौड़ में अमेरिका के सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेजा था। राष्ट्रपति रीगन के शब्दों में, अमेरिका में आपकी पृष्ठभूमि को नहीं, सपनों को महत्व दिया जाता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। इस अकादमिक आजादी पर बंदिशों और निगरानियों के अंकुश लगाने पर प्रतिभाएं दूसरे ठिकाने खोज लेंगी। हिटलर के जमाने तक विज्ञान और अनुसंधान में सबसे बड़ी शक्ति जर्मनी था। विज्ञान के एक तिहाई नोबेल पुरस्कार जर्मन जीतते थे, जिनमें अधिकांश यहूदी होते थे। हिटलर के अत्याचारों से भागकर वे सब अमेरिका चले गए और तब से अमेरिका विज्ञान एवं अनुसंधान की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ है। विज्ञान के 41 प्रतिशत से अधिक नोबेल पुरस्कार अमेरिकी जीतते हैं। दुनिया की सौ चोटी के विश्वविद्यालयों में से 36 अमेरिका के हैं, जो अमेरिका की आर्थिक-सामरिक शक्ति की निर्माणशालाएं हैं। अमेरिका के इस एकछत्र राज में अब चीन सेंध मार रहा है। विज्ञान के 82 प्रतिष्ठित शोधपत्रों में छपने वाले शोध लेखों की गुणवत्ता और संख्या के आधार पर शोध संस्थाओं का वर्गीकरण नेचर पत्रिका करती है। इसमें शामिल पहली 10 शोध संस्थाओं में हार्वर्ड को छोड़कर बाकी नौ चीन की हैं। गनीमत है कि हार्वर्ड इस तालिका में चोटी पर है। नए आविष्कारों के पेटेंट के मामले में तो अमेरिका चीन के आसपास भी नहीं। उनके लिए करीब आधे आवेदन अब अकेले चीन से आते हैं। हां, प्रतिभाओं को आकर्षित करने में अमेरिका अब भी चीन से बहुत आगे है। हर साल दुनिया के 11 लाख से अधिक प्रतिभावान छात्र पढ़ने और शोध करने अमेरिका आते हैं। इनमें से एक तिहाई अकेले भारत के होते हैं। विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकियों में से एक तिहाई आप्रवासी होते हैं। साफ्टवेयर बनाने वालों में 40 प्रतिशत आप्रवासी हैं और कैंसर संस्थानों में 60 प्रतिशत तक आप्रवासी विज्ञानी हैं। अमेरिका की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से पांच के प्रमुख आप्रवासी हैं। इनमें से दो भारतवंशी हैं।

अवधेश राजपूत

चिंता इसकी है कि विश्वविद्यालयों के खिलाफ छिड़ी जंग से अमेरिका चीन पर हासिल अपनी उस बढ़त को भी गंवा सकता है, जो उसे विश्व की प्रतिभाओं को आकर्षित करने में हासिल है। विश्वविद्यालयों में विदेशी प्रतिभाओं का आना कम होने के साथ अमेरिकी प्रतिभाओं का पलायन भी शुरू हो गया है। गत अप्रैल में नेचर पत्रिका के एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 1,600 से अधिक अमेरिकी विज्ञान शोधकर्ताओं में से 75 प्रतिशत ने कहा कि वे अमेरिका छोड़कर यूरोप, कनाडा और आस्ट्रेलिया जाने पर विचार कर रहे हैं। हार्वर्ड समेत अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले हजारों भारतीय छात्रों को अमेरिका में अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पैदा हुए संकट का भारत के लिए सबसे बड़ा सबक और अवसर यह है कि इसे अपने छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार का स्तर सुधारना और उसे परिणामोन्मुखी बनाना चाहिए। भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के सौ श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में नहीं है। जब चीन के पांच विश्वविद्यालय इस तालिका में स्थान पा सकते हैं तो भारत के क्यों नहीं? देश का विकास केवल तक्षशिला और नालंदा की महत्ता गाने से नहीं, आज की यूनिवर्सिटियों को वैसा बनाने और यह सुनिश्चित करने से होगा कि वे राजनीति के अखाड़े बनने की जगह प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार के केंद्र बनें।

(लेखक बीबीसी हिंदी के संपादक रहे हैं)

response@jagran.com

पाकिस्तानी जासूसों का मकड़जाल

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से 26 निर्दोष भारतीयों की उनका मजहब पूछकर हत्या करने और आपरेशन सिंदूर के बाद से देश के अनेक हिस्सों से एनआइए सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, असम आदि राज्यों में करीब दो दर्जन पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए हैं। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सर्वाधिक चर्चित ज्योति मल्होत्रा है। वह एक ट्रैवल ब्लागर है। वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग गई थी। वह अन्य मौकों पर भी वहां जाती थी। वह कई बार पाकिस्तान गई और वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ से भी मिली। उसके साथ जसबीर सिंह को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह भी ब्लागर है।

विक्रम सिंह

आइएसआइ के मंसूबों को विफल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और सर्विलांस उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए

जासूसी के आरोप में पकड़ा गया हरियाणा का तारीफ। फाइल

इनके अलावा कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें एक है रविंद्र मुरलीधर वर्मा, जो मुंबई में सुरक्षा ठेकेदार था। आरोप है कि उसने नौसेना के 14 जहाजों सहित सामरिक महत्व की कई जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलरों को दी। वर्मा अपने कार्यालय जाकर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मानचित्रों, सूचनाओं और अभिलेखों को किसी तरह अपने लैपटाप के जरिये आइआसआइ के एजेंटों को भेजता था। एक अन्य अमन यादव को भी एनआइए ने जासूसी के आरोप में गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ के मोतीराम जाट को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। यूपी एटीएस ने रामपुर से जिस शहजाद को गिरफ्तार किया, उसका पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों से संबंध था। यही कहानी हरियाणा के तारीफ की है। वह पांच बार पाकिस्तान गया और फिर एक लाख रुपये के लालच में उसने सेना के ठिकानों की जानकारी पाकिस्तानी उच्चायोग के उस अधिकारी को दी, जो उसे और उसके दोस्तों को पाकिस्तान का वीजा दिलाता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में अजनाला के दो ऐसे लोग भी हैं, जो पहले दलित थे और फिर ईसाई बन गए थे। यह इसलिए हैरान करता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ईसाइयों पर बहुत अत्याचार होते हैं। नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मुर्तजा अली, सुखप्रीत, करनबीर, यासीन, गजाला खातून, सूरज मसीह जैसे अन्य लोग भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यह सिलसिला अब भी कायम है।

ट्रैवल ब्लागर से लेकर सुरक्षा गार्ड, एप डेवलपर, आम नागरिक तक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं, जो हनी ट्रैप या पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ को लीक कर रहे थे। महाराष्ट्र में 65 साल के साकिब ने तो हद ही कर दी। 1993 के मुंबई एवं अन्य बम विस्फोटों में वह पोटा और टाडा में दस-दस साल की सजा काट चुका है। वह अफगानिस्तान जाकर अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर रूसी सेना से युद्ध भी कर चुका है। 2023 में जब एनआइए ने उसके यहां छापा मारा, तो उसके घर से आइएसआइएस के झंडे, एके-47, तलवार और जिहादी सामग्रियां मिलीं। वह आइएसआइएस की सदस्यता और समर्थन की शपथ भी ले चुका था। उसने अपने गांव पगड़ागांव का नाम बदलकर अलशाम रख लिया था और उसे सीरिया की तरह स्वतंत्र क्षेत्र बनाना चाहता था। प्रतीत होता है कि उसके अतीत को देखते हुए उसकी जिस स्तर की निगरानी होनी चाहिए थी, वह नहीं की गई। ऐसे तत्वों की निगरानी का स्तर तो उच्च कोटि का होना चाहिए।

प्रत्येक थाने में एक लापता पाकिस्तानी नागरिक रजिस्टर होता है, जिसमें पाकिस्तान के ऐसे नागरिकों का लेखा-जोखा होता है, जो भारत तो आते हैं, परंतु भूमिगत हो जाते हैं या लापता हो जाते हैं। ऐसे तत्वों पर नजर रखी जानी चाहिए। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी से यह पता चलता है कि पाकिस्तान कैसे जासूस तैयार करता है। आइएसआइ चार तरीकों से भारत में अपना जासूसी तंत्र खड़ा कर रही है। सबसे पहला है धन का प्रलोभन। दूसरा माध्यम है लोकप्रियता और प्रसिद्धि दिलाने का लालच। जैसे जसबीर सिंह, ज्योति मल्होत्रा के फालोवर्स की संख्या बढ़ाने में आइएसआइ का योगदान रहा। इसके अलावा हनी ट्रैप के माध्यम से भी कई भारतीय नागरिकों को फंसाकर जासूसी कराई जाती है। अंतिम बिंदु है जिहाद का। इसके तहत आइएसआइ गजवा-ए-हिंद पर यकीन रखने या कट्टरपंथी सोच वालों को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करती है। इसके लिए वह जिहादी साहित्य के जरिए उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए उनका ब्रेनवाश करती है। यह स्थिति गंभीर है और बताती है कि भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जासूसी के इस मकड़जाल को तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और सर्विलांस उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान और आइएसआइ के मंसूबे विफल हों और भारत सुरक्षित रहे।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अभाव मुक्त जीवन

एक महत्वपूर्ण कथन है- ''सबकुछ तो किसी के पास नहीं होता, पर कुछ न कुछ हर एक के पास होता है।'' इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए, जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों पर, जो हमारे पास नहीं हैं, अन्यथा जीवन की दौड़ कभी थम नहीं पाएगी। और किसी ने किसी चीज का अभाव बना रहेगा।

जब हम किसी एक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, तो थोड़े समय बाद हमें दूसरी वस्तु के अभाव का अनुभव होने लगता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है- दृष्टिकोण में बदलाव। सही दृष्टिकोण के अभाव में जीवन में अभाव ही अभाव रहता है। जब हम समाज में दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। यह सोच हमें हीनता की भावना से भर देता है और नकारात्मकता को जन्म देता है।

अभावों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति को पहचानना चाहिए। दूसरों से तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं और विचार भिन्न होते हैं। अभावों को दूर करने के लिए हमें अपनी जीवन की वास्तविकता को भी पहचानना चाहिए और जीवन को उसकी विविधता के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी के जीवन का एक पक्ष मजबूत होता है, तो किसी का दूसरा पक्ष। अपने नजरिए में बदलाव लाकर, अपनी योग्यता और श्रम से हम अपने अभावों को दूर कर सकते हैं। अभावों को याद करके दुखी होना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को अभावों से मुक्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें।

अवधविहारी शुक्ला

विकसित बनना है तो स्वदेशी अपनाएं

ठेंद्रराज सुथार

जब हम देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे, तभी भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी

गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में चौथे से तीसरे स्थान पर लाने के लिए हर भारतीय को यह संकल्प लेना होगा कि वह विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा। वर्तमान व्यापार आंकड़े देश की आर्थिक संरचना में गहरा असंतुलन दर्शाते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत ने चीन से 113.5 बिलियन डालर का आयात किया, जबकि निर्यात केवल 1.5 बिलियन डालर रहा। यह करीब 100 बिलियन डालर का व्यापार घाटा है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आयात ऐसी वस्तुओं का है, जिन्हें भारत में आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे बटन, पेन, कंघी, टायलेट पेपर, पेंटिंग की किताबें, खिलौने, टिश्यू, वालपेपर और नोटबुक आदि। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके निर्माण के लिए न तो अत्यधिक तकनीकी जटिलता की जरूरत होती है, न ही ज्यादा पूंजी निवेश की। पिछले दो दशकों में चीन ने अपने घरेलू उत्पादन को मजबूत किया और हजारों छोटी औद्योगिक समस्याओं का समाधान कर खुद को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया, साधारण रोजमर्रा की वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दी। इस रणनीति के जरिए न केवल रोजगार पैदा किए, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत की। भारत को भी इस माडल को अपनाना होगा और गहन विनिर्माण नीति पर जोर देना होगा। इसके लिए कच्चे माल की लागत कम करना, स्थानीय उद्योगों को सस्ता और निर्बाध वित्तपोषण और तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जरूरी है।

भारत के पास क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। फार्मास्युटिकल सेक्टर इसका सुबूत है, जहां भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर वैश्विक बाजार में अपनी श्रेष्ठता साबित की। यही क्षमताएं अन्य क्षेत्रों में भी हैं, जरूरत है तो सिर्फ नीति, नीयत और नागरिक भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने जो विचार उठाया है कि हर गांव और शहर में व्यापारियों को शपथ दिलाई जाए कि वे कितना भी मुनाफा कमाएं, विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, यह बाजार की दिशा बदलने की व्यावहारिक रणनीति है। जब ग्राहक विदेशी सामान मांगना बंद कर देंगे, तो व्यापारी भी उन्हें मंगाना बंद कर देंगे। यह भी स्पष्ट है कि सरकार चीन जैसे देशों से आयात पर सीधे अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का पालन करता है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। हर व्यक्ति को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि वह रोजाना कितनी विदेशी वस्तुओं का उपयोग करता है और उनमें से किन वस्तुओं को स्थानीय उत्पादों से बदला जा सकता है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग न केवल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होना चाहिए, बल्कि यह गुणवत्तापूर्ण, प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकल्प भी होना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

संस्कृति के प्रति नव आस्था का संचार

''सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल'' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में स्वामी अवधेशानंद गिरि ने बताया है कि 2014 से अब तक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्र की आत्मिक चेतना के पुनर्स्थापन का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। देखा जाए तो भारत आज केवल एक भौगोलिक सत्ता नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है। बीते एक दशक ने यह प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व में संस्कृति के प्रति श्रद्धा हो, तो राष्ट्र आत्मगौरव से दीप्त हो उठता है। यह कालखंड केवल विकास की भौतिक गाथा नहीं, अपितु आत्मा से जुड़े राष्ट्र के नवजीवन की कथा है। भारत की जड़ें सदियों पुरानी हैं, परंतु उन्हें पुनः हरा-भरा करने की आवश्यकता थी। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, सनातन मूल्यों का सम्मान और एकता की अंतःसलिला को पुनः प्रवाहित करने का यत्न कर यही किया जा रहा है। आध्यात्मिक स्थलों का नवाचार केवल इमारतों का सौंदर्य नहीं, जनमानस में संस्कृति के प्रति नव आस्था का संचार है। देश की विदेश नीति हो या आंतरिक परियोजनाएं, सबमें भारतीयता की छाप स्पष्ट है। हर कलाकृति की वापसी, हर स्मारक का पुनरुद्धार, एक संदेश है भारत अपनी जड़ों से कटकर नहीं, जुड़कर बढ़ेगा। इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को और व्यापक बनाने हेतु अब समय आ गया है कि हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन, संस्कृति और इतिहास के गौरवपूर्ण पक्षों को यथोचित स्थान दें। स्थानीय भाषाओं, लोककलाओं और ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु एकीकृत राष्ट्रीय नीति बने। प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हों। डिजिटल माध्यमों से भारतीय परंपराएं वैश्विक युवा मन तक पहुंचें। साथ ही प्रवासी भारतीयों को 'सांस्कृतिक दूत' बनाकर भारत की आत्मा को विश्वपटल पर प्रस्तुत करने की संगठित पहल हो।

अमन सिंह गौर, छात्र, बीएचयू

मेलबाक्स

मोदी सरकार की सफलता

संपादकीय 'तीसरे कार्यकाल का पहला साल' में मोदी सरकार के जारी कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। बात चाहे वक्फ बिल संशोधन की हो, या एक देश- एक कानून की, या फिर बात एक देश-एक चुनाव की हो या माओवाद मुक्त अभियान की हो या आपरेशन सिंदूर की, या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हो या 11 वर्षों में 27 करोड़ गरीबों के उत्थान की, यह सरकार हर मोर्चे पर जनता की उम्मीदों, अपेक्षाओं और भावनाओं पर खरी उतरी है। गठबंधन सरकार के सहयोग से बहुमत हासिल करने के बावजूद सरकार ने जनहितैषी योजनाओं को लागू करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी या दबाव में फैसले नहीं लिए, उनका हर कदम जनता की जरूरतों की पूर्ति के लिए ही आगे बढ़ा है।

मोहित सोनी, कुक्षी, मप्र

भारत में न्यायपालिका

भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, जो संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का कार्य करती है। लेकिन हाल के वर्षों में न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और संभावित महाभियोग की चर्चा ने इस मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त हो। संवैधानिक संस्थाओं को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। अब समय आ गया है कि न्यायपालिका खुद अपने भीतर एक स्वतंत्र जांच प्रणाली विकसित करे, जो भ्रष्टाचार और लोक शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सके। लोकतंत्र की नींव तभी मजबूत रह सकती है, जब न्यायपालिका निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे। आज जरूरत है कि न्यायपालिका आत्ममंथन करे और जनता का खोया विश्वास पुनः अर्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

चिंतन

आतंकवाद पर एक्शन के बिना सिंधु जल संधि पर बात नहीं

आतंकवाद पर भारत का स्पष्ट संदेश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगा। पाकिस्तान को अब तक समझ जाना चाहिए कि वह जब तक आतंकवाद के खिलाफ संतोषप्रद कार्रवाई नहीं करता है, तब तक वह भारत से कोई अपेक्षा नहीं करे। पहलगाम में नृशंस आतंकी घटना के बाद भारत ने आतंकवादियों, आतंकी गुटों व दहशतगर्द की साजिश रचने वालों के खिलाफ कई कदम उठाए। कश्मीर स्थित आतंकी गुट द रेजिसटेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्करे तैयबा का छद्म गुट है, इससे साफ हो गया था कि पहलगाम आतंकी हमले में पाक के आतंकी गुट का हाथ है। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के ट्रेड बंद किए, सीमा को बंद किया, पाक नागरिकों को वापस भेजा, उच्चायोग से कर्मियों की संख्या में कटौती की और सिंधु जल समझौते को निलंबित किया। ऑपरेशन सिंदूर लांच करके भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए। अभी दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी है, लेकिन भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित ही रखा है। भारत ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि भारत सिंधु जल संधि पर तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा, जब तक कि आतंकवाद के संबंध में नई दिल्ली की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता और संधि को पूरी तरह से नया रूप नहीं दे दिया जाता। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने कई बार भारत से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अपनी भारतीय समकक्ष देबाश्री मुखर्जी को लिखे कई पत्रों में मुर्तजा ने बार-बार अपनी सरकार की ओर से नई दिल्ली द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। अभी भारत ने पाकिस्तान के किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। मुखर्जी ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इस फैसले से अवगत कराया था। सिंधु जल संधि के मुताबिक, भारत से पाकिस्तान को सिंधु, झेलम व चिनाब नदियों के 80 फीसदी जल पहुंच रहे थे, भारत केवल 20 फीसदी ही अपने पास रख रहा था। इस समझौते के स्थगित होने से अब भारत बाध्य नहीं है। इन तीन नदियों के जल से न केवल पाकिस्तान के लोगों की प्यास बुझती है, बल्कि बड़े हिस्से में सिंचाई भी होती है। पूर्व में भारत और पाकिस्तान के संबंध कई बार खराब हुए, लेकिन भारत ने कभी जल प्रबंधित नहीं किया। इस बार पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। भारत लंबे समय से आतंकी गुटों के खात्मे के लिए पाकिस्तान से कह रहा है, भारत में अनेक आतंकी हमले में पाकिस्तान की एस्टाब्लिशमेंट के हाथ रहे हैं, भारत ने डोजियर के जरिये इसके सबूत भी दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी जमीं से आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अब भारत ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने यहां से आतंकवाद का सफाया करे, भारत को आश्वस्त करे कि उसकी एस्टाब्लिसमेंट (फौज और आईएसआई) सीमा पार से कोई भी आतंकी हरकत नहीं करेगी, इसके बाद ही जल समझौते के निलंबन को हटाने पर विचार होगा। पाकिस्तान को कड़ा सबक देना जरूरी है, भारत पाक प्रायोजित आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है।

आतंकवाद के खात्मे को केंद्र प्रतिबद्ध

दो टूक
सुरेश पचौरी

> ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण को एक माह पूरा होने जा रहा है। देशवासियों ने भारत की बहादुर सेना के अद्भुत पराक्रम को देखा है, लेकिन विपक्ष के कतिपय नेताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं वे न तो सामयिक हैं और न ही उनका कोई औचित्य दिखता है। जो प्रमुख प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वे हैं : सीजफायर क्यों किया गया? क्या इस फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव डाला? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कितनी सैन्य क्षति हुई? इस विषय में चर्चा के लिए संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये सवाल आज की परिस्थितियों में गैरवाजिब है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है। इस कामयाबी का पूरा श्रेय भारतीय सेना को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण को एक माह पूरा होने जा रहा है। देशवासियों ने भारत की बहादुर सेना के अद्भुत पराक्रम को देखा है, लेकिन विपक्ष के कतिपय नेताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं वे न तो सामयिक हैं और न ही उनका कोई औचित्य दिखता है। जो प्रमुख प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वे हैं : सीजफायर क्यों किया गया? क्या इस फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव डाला? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कितनी सैन्य क्षति हुई? इस विषय में चर्चा के लिए संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये सवाल आज की परिस्थितियों में गैरवाजिब हैं। इन सारे सवालों के उत्तर उचित फोरम पर दिए जा चुके हैं।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस एवं तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ लगातार बैठकें की, रणनीति बनाई, लक्ष्य निर्धारित किया और आतंकवादियों के सफाये का अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। 7-8 मई की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान में लगभग 100 किलोमीटर घुसकर लक्षित हमला किया, जिसमें आतंकियों के नौ ठिकानों, उनके प्रशिक्षण शिविरों तथा पाक एयरबेस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने राफेल जेट, एससीएएलनी मिसाइलों तथा हैमर बमों का उपयोग करके केवल 22 मिनट में मिशन पूरा किया। वस्तुतः पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। यह सामान्य साहस की बात नहीं है। दूसरी ओर आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के अनेक नेताओं, उच्च अधिकारियों तथा पाक सेना प्रमुख के शामिल होने से फिर इसकी पुष्टि हो गई कि आतंकवादियों के पाक सेना से बहुत गहरे संबंध है।

यह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है कि महज 3-4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और युद्ध रोकने की गुहार करने लगा। भारतीय सेना से गहरी मार खाने के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से 10 मई 2025 को निवेदन किया और अंततः भारत ने अपनी जबावी कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कतर देश की यात्रा के दौरान स्वयं कहा है कि मैं यह नहीं कहता कि मैंने मध्यस्थता की है। ट्रंप के कथन को लेकर भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेनाध्यक्षों ने जो सही वस्तुस्थिति बताई है, भरोसा उस पर ही किया जाना चाहिए। सीडीएस अनिल चौहान ने स्वयं कहा है कि इस युद्ध में भारत की एकतरफा जीत हुई है। सेना के शीर्ष नेतृत्व की बात ही युद्ध के संदर्भ में मानी जानी चाहिए। जहां तक संसदीय सत्र बुलाने की बात है, देश की सुरक्षा और युद्ध ऐसे संवेदनशील विषय हैं जिन पर सार्वजनिक चर्चा से यथासंभव बचना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के कई सकारात्मक पक्ष सामने आए हैं। पहला है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरा सटीक और पुख्ता इन्टेलिजेन्स, तीसरा भारतीय सेना की प्रोफेशनल क्षमता और चौथा देश की एकजुटता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में, फिर 13 मई को आदमपुर में और इसके बाद बीकानेर में भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं। हम पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने इस बात को कई बार जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत, व्यापार और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चलेगा। अगर यह युग युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं हैं, इससे पूरी दुनिया त्रस्त है।

प्रधानमंत्री की स्पष्ट घोषणा है कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीमा पर प्रोक्सीवॉर नहीं चलेगा। पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी, तो उसका एजेंडा आतंकवाद की समाप्ति एवं पीओके होगा। भविष्य में आतंकवादी घटनाएं हुई तो उसे 'एक्ट ऑफ वॉर' मानकर ही कार्रवाई होगी। हम गोली का जबाब गोलों से देंगे। प्रधानमंत्री के इस तरह दो टूक वक्तव्यों के बाद अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अनेक देशों में भेजा और उन सदस्यों ने जिस कुशलता से भारत का पक्ष रखा उससे उन देशों के मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। दूसरी ओर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सुश्री कनीमोजी, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी और अस्सुद्दीन ओवेसी आदि पर कुछ लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर कांग्रेस के ही कुछ लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवाल दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

स्मरणीय है कि 1994 में पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत को घेरने की रणनीति बनाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बनाकर जिनेवा भेजा था। अटल की बुद्धिमत्ता, उनकी तर्कपूर्ण पैरवी और नरसिंह राव की कूटनीति के सामने पाकिस्तान का झूठ टिक नहीं पाया। जो दायित्व देशहित में अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी नेता के रूप में उस समय निभाया था, वही दायित्व अभी कांग्रेस के शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनन्द शर्मा, मनीष तिवारी ने निभाया है, और इन्होंने पाक को बेनकाब किया है। कांग्रेस के जो नेता अपने साथियों की प्रतिनिधिमंडल में भूमिका पर तरह-तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, यह अनुचित है, चूंकि पाकिस्तान इस तरह के वक्तव्यों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में उपयोग करता है।

यह भी याद रखना होगा कि 26 नवम्बर, 2008 को जब लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई पर सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जानें गई थीं उस समय तत्कालीन सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की थी? आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर अनावश्यक प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार की भूमिका से भी इसकी तुलना होगी।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

दरकार

मानस गर्ग

सख्त डाटा सुरक्षा कानून बने

रमेश कुमार का मोबाइल फोन इन दिनों हर कुछ मिनट में घनघनाता रहता है। वो बेहद परेशान हैं। आखिर उनका मोबाइल नंबर कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास पहुंच गया? कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को यह जानकारी मिल गई कि उनकी बेटी ने कक्षा 12 की परीक्षा पास की है? यह पीड़ा केवल अकेले रमेश कुमार की नहीं है, देशभर में ऐसे लाखों अभिभावक हैं, जिनका डाटा कहीं न कहीं साझा कर दिया गया है। न केवल मार्केटिंग कंपनियों के पास आम नागरिक का डाटा है, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंडस्ट्री और ऐसी अनेक ऑर्गेनाइजेशन्स की आम नागरिक के डाटा तक आसान पहुंच बन चुकी है। शायद यही कारण है कि भारत सरकार को डाटा गोपनीयता को लेकर नया कानून लाने पर विचार करना पड़ा है। जनवरी 2025 में इसका एक ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि क्या डाटा गोपनीयता कानून के बाद लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस अंदाज में कंपनियां हमारे डाटा को लेकर व्याकुल हैं, उन्हें शांत करना आसान नहीं होगा। सरकार को बेहद कड़े कदम उठाने होंगे। अब एक नागरिक की पहचान केवल आधार नंबर या पेन कार्ड भर से नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल उपस्थिति से भी उसकी पहचान गाढ़ी जा रही है। फिर वही सवाल, क्या डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए आम नागरिक के पास कोई अधिकार है? क्या आम नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसका डाटा कहां, कैसे और क्यों इस्तेमाल हो रहा है? दरअसल, मार्केटिंग कंपनियों और कई संस्थाओं के लिए हमारा डाटा एक नया फ्यूल बन गया है। इसे विज्ञापन प्रोफाइलिंग और कई बार धोखाधड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिजिलॉकर से आधार नंबर संबंधी डिटेल्स बाहर आने के कई मामले सामने आए हैं, इसलिए डाटा की सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा भर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक नीतिगत और नैतिक विषय भी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से देश में सीमा पार से साइबर अटैक बढ़े। साइबर अपराधी आम नागरिक के बैंक अकाउंट में सेंध लगा लेते हैं। केवल डाटा सुरक्षा नहीं, साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार को बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब जरा, यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) पर नजर डालते हैं। वर्ष 2018 में यूरोपीय संघ ने इसे लागू किया था, जिसमें डाटा को निजात का हिस्सा और मानवाधिकार माना गया। इस यूरोपीय मॉडल के अनुसार नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं। उनकी बिना अनुमति डाटा नहीं लिया जा सकता। आम नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है कि कौन डाटा रख रहा है और क्यों रख रहा है? वह उपयोगकर्ता से अपने डाटा को मिटवा भी सकता है। एक सेवा से दूसरी में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भी इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे डीपीडीपीए भी कहा जाता है, को पारित किया। यह कानून यूरोपीय संघ के जीडीपीआर से प्रेरित है, लेकिन भारत की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार इसे तैयार किया गया है। डीपीडीपीए के तहत आम नागरिक को सहमति का अधिकार है, यानी बिना उसकी स्पष्ट अनुमति के कोई डाटा नहीं लिया जा सकता है। उसे यह जानने का अधिकार है कि कौन, क्यों और कैसा डाटा इस्तेमाल कर रहा है? उसे सुधार और हटवाने का अधिकार है। उसे शिकायत का अधिकार दिया गया है, यानी यदि उसके डाटा का दुरुपयोग हुआ है तो शिकायत की करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि जीडीपीआर और डीपीडीपीए का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाएंगे कि जहां जीडीपीआर में डाटा की परिभाषा व्यापक और स्पष्ट है, वहीं डीपीडीपीए में कुछ मामलों में अस्पष्टता नजर आती है। भारत जैसे देश में डिजिटल साक्षरता अभी भी बड़ी चुनौतियों भरी है। भारत में डीपीडीपीए का सफल क्रियान्वन तभी होगा, जब शिक्षा, जन-जागरुकता और टेक्नोलॉजिकल जवाबदेही साथ-साथ चलें। डीपीडीपीए-2023 भारत के डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह न केवल बड़ा तकनीकी बदलाव है, बल्कि सामाजिक और नैतिक घोषणा भी है। भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ डाटा उपभोक्ता भर नहीं, बल्कि उसका स्वामी भी है। भारत में मौलिक अधिकारों में डाटा नियंत्रण को भी शामिल करने की जरूरत है। डाटा सुरक्षा का विषय स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए। जिस तरीके से कंपनियों की पहुंच डाटा तक आसानी से हो रही है, यह चिंतनीय है। उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार ठोस कदम उठाएगी, ताकि आम नागरिक का डाटा सुरक्षित रहे। बिना उसकी अनुमति के उसके डाटा का उपयोग न हो सके।

(लेखक साइबर सिक्योरिटी एवं आईटी एक्ट के विशेषज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या चाहती है

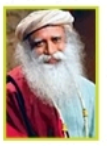

संकलित
दर्शन

क्या जिंदगी की पुकार, जैसा कुछ होता है? कैसे जानें कि हमारी जिंदगी हमसे क्या चाहती है? सद्गुरु- मैं चाहता हूं कि यह आप ठीक से समझ लें, कि जिंदगी की पुकार जैसी चीज तो नहीं होती, लेकिन जिंदगी आपको हमेशा पुकार रही है, आपसे कुछ कह रही है, भीतर से भी और बाहर से भी। जब आप जीवन की पुकार का सचमुच जवाब देंगे, तभी आप जीवन को उसकी संपूर्णता में जान पाएंगे। अगर जीवन आपको पुकार रहा है, तो बड़ी लगन और जुनून से आपको उसकी तरफ जाना होगा, हिचकिचा कर हिसाब लगाते हुए नहीं।इसलिए नहीं कि आपका अहं जो हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखता है, तुष्ट हो सके। बल्कि इसलिए कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। अगर जिंदगी के हर पहलू को ले कर आपमें एक जुनून है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आप किस काम में अच्छे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे काम में अच्छे हों, जो आपने अभी तक किया ही न हो। हर उस चीज में जोश व जुनून के साथ शामिल होना चाहिए, जिसे आपकी पांचों इंद्रियां महसूस कर सकती हों। यह जुनून सबको अपने में शामिल कर लेने वाला होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो यही करुणा है। करुणा का मतलब दया भाव नहीं है, यह तो एक साधन है, बिना किसी पूर्वाग्रह के शामिल होने का। जिस क्रम में जीवन घटित होता है, उसमें सबसे पहले है होना, फिर करना और तब पाना। लेकिन आजकल लोग हमेशा सबसे पहले पाने के बारे में सोचते हैं।

प्रेम के पांच पुष्प बाण यानी हमारी इंद्रियां

संकलित
प्रेरणा

भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम के देवता का एक नाम अनंग है। अनंग का अर्थ है, जिसके शरीर का कोई अंग न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम निराकार होता है। उसके पास एक धनुष और पांच बाण रहते हैं। ये पांच बाण पांच फूलों से बने होते हैं यानी हमारी पांच इंद्रियां। और जब वे इन पांच फूलों से तुम्हें छूता है, तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तुम कुछ ऐसा अनुभव करते हो जो इंद्रियों से परे है। और तुम्हारे भीतर गहराई में एक सौंदर्य की लहर उठती है जो मधुर शहद की तरह रस पैदा करती है। जब आप कुछ भी अद्भुत अनुभव करते हैं, चाहे वह संगीत हो या कोई सुगंध या किसी प्रियजन का संपर्क तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और आप सौंदर्य के सागर में डूब जाते हैं। आप अपने स्वभाव में आ जाते हैं। ऐसे क्षणों में आप साकार से निकलकर उस निराकार में विलीन हो जाते हैं। आपके भीतर ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगती है। जैसे ध्यान में उत्थान का आभास होता है, चिरस्थायी आनंद का अनुभव होता है। जिस तरह वसंत ऋतु में सारी सृष्टि खिल उठती है, पक्षी गाते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, वैसे ही जब आपके भीतर ऊर्जा जागती है, तो विस्मय होता है। आप आलस्य और जड़ता त्याग देते हैं और नए जीवन का उदय होता है। अगर यह ऊर्ध्वगमन जीवन में न हो, तो आप नीरस हो जाते हैं। और इंद्रियों का अत्यधिक उपभोग करते-करते आप और भी जड़ हो जाते हैं। सृष्टि आपकी पांच इंद्रियों पर पांच बाणों से चोट करती है, आपके भीतर गहराई में सौंदर्य की भावना जगाने के लिए।

अंतर्मन

आज की पाती

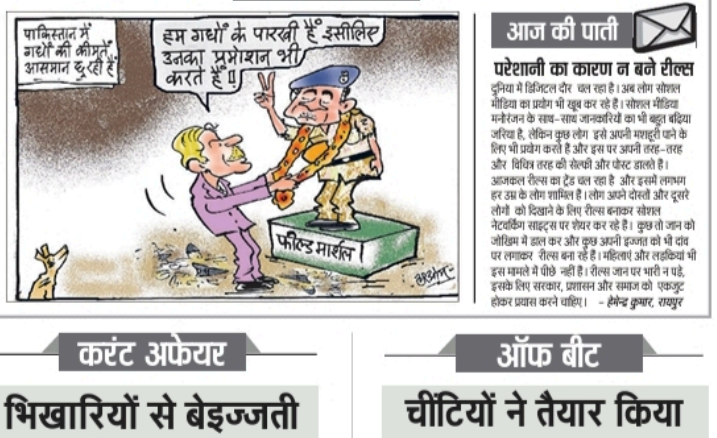

परेशानी का कारण न बने रील्स

दुनिया में डिजिटल दौर चल रहा है। अब लोग सोशल मीडिया का प्रयोग भी खूब कर रहे हैं। सोशल मीडिया मनोरंजन के साथ-साथ जानकारियों का भी बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी मशहूरी पाने के लिए भी प्रयोग करते हैं और इस पर अपनी तरह-तरह और विचित्र तरह की सेल्फी और पोस्ट डालते हैं। आजकल रील्स का ट्रेंड चल रहा है और इसमें लगभग हर उम्र के लोग शामिल हैं। लोग अपने दोस्तों और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए रील्स बनाकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर कर रहे हैं। कुछ तो जान को जोखिम में डाल कर और कुछ अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाकर रील्स बना रहे हैं। महिलाएं और लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं है। रील्स जान पर भारी न पड़े, इसके लिए सरकार, प्रशासन और समाज को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। - हेमेन्द्र कुमार, रायपुर

ट्रेंड

सेवाभाव के ग्यारह साल

बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव से लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

चुनाव आयोग का अच्छा कदम

मतदाता सूची सौंपने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया पहला अच्छा कदम। क्या चुनाव आयोग कृपया यह बता सकता है कि वह डेटा डिजिटल, मशीन-पठनीय प्रारूप में कब तक सौंप दिया जाएगा?
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करती प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना, जन धन योजना आमजन के जीवन को सुगम बनाने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
-योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी

ऐसे लोगों से दूर रहें

उन लोगों से दूर रहें जो आपको थका देते हैं। ऐसी बहसों से दूर रहें जो कभी खत्म नहीं होती। अपनी योग्यता साबित करने के लिए लोगों को खुश करने की कोशिश न करें। नकारात्मकता से दूर जाने वाला हर कदम शांति की ओर एक कदम है।
-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

भिखारियों से बेइज्जती कार्रवाई करेगी पाक सरकार

सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में भिखारियों को लेकर पाकिस्तान की फजीहत अब आम बात हो गई है। फटेहाल पाकिस्तान के भिखारी यूएई, कतर, ओमान, इराक और मलेशिया जैसे देशों से भी भगाए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने बीते 16 महीनों में 5 हजार से अधिक पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। भिखारियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती झेल रहे पाकिस्तान ने डिपोर्ट किए गए अपने लोगों के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय भिखमंगी सिंडिकेट का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भिखारियों का पासपोर्ट कैंसिल करने, उन पर पांच साल का ट्रैवल बैन लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। डिपोर्ट किए गए 7,873 भिखारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के 2.2 करोड़ लोग भिखमंगी में संलिप्त हैं जो हर साल 42 अरब पाकिस्तानी रुपये का योगदान देते हैं। पाकिस्तान के भिखारी विदेशों में भीख मांगकर लाखों कमाते हैं जो देश की जीडीपी का अहम हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान भिखारियों के मुद्दे पर तब तक आंख मूंदे था।

ऑफ बीट

चींटियों ने तैयार किया था मंदिर का नक्शा

हिमाचल प्रदेश के करसोग की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय मंदिर है चिंडी माता मंदिर। इस मंदिर की देवी मां चंडी हैं। ये मंदिर शिम्ला के रास्ते पर करसोग से 13 किमी. पीछे स्थित है। वहीं ये रहस्यमय मंदिर हिमालय के आकर्षण का केंद्र भी है। चिंडी माता मंदिर को कई चीजें खास बनाती हैं। जैसे इसका रहस्यमयी इतिहास, प्राचीन आठ भुजाओं वाली पत्थर से बनी मूर्ति। कहा जाता है कि निःसंतान का मां संतान का वरदान देती है, वहीं कहा जाता है कि चिंडी माता मंदिर का नक्शा किसी इंसान के हाथ से नहीं, बल्कि मेहनती चीटियों ने तैयार किया था। सदियों से चल रही कहानियों की मानें तो माता रानी कन्या रूप में प्रकट हुई थी। चीटियों की डोर बनाकर नक्शा तैयार किया था और माता ने मंदिर का निर्माण खुद किया था। मान्यताओं के अनुसार नक्शे की जानकारी माता ने पंडित को स्वप्न में आकर दी थी। इतना ही नहीं उसके बाद मंदिर के तालाब और भंडार का नक्शा भी चीटियों ने ही बनाया था। ये मंदिर लकड़ी से बना है और देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर लगता है, इस मंदिर में कई मंजिलें हैं, छतों पर कुलदेवताओं के प्रतीक उकेरे गए हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाले निःसंतान भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है।

ट्रंप-मस्क संबंध
टकराव जारी

डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क को एक समय अमेरिका को बदलने वाली शक्ति माना जाता था, पर अब उनके बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। नाटकीय ढंग से घटनाक्रम बदलने के बाद अब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खरबपति उद्योगपति इलोन मस्क ने संबंध तोड़ लिए हैं और इस प्रकार रणनीतिक सहयोगी कट्टर सार्वजनिक-विरोधी बन गए हैं। विनियमन, सरकार की कार्यक्षमता तथा अवस्थापना-विरोधी बयानबाजी में साझा लाभदायक संबंध अब दुश्मनी, मतभेद, व्यक्तिगत हमलों, नीतिगत टकरावों और राजनीतिक धमकियों में बदल गए हैं जो 2026 के मध्यकालीन चुनावों को नया स्वरूप दे सकते हैं। एक समय यह गठबंधन असंभव लगता था जिसमें ट्रंप अपनी आक्रामक राजनीतिक शक्ति तथा मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स व सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के साथ दूरदर्शी तकनीकी शक्ति के रूप में उपस्थित थे। वे अलग-अलग दुनिया से आते थे, पर उन्होंने साझा आधार तलाश लिया था। ट्रंप मस्क की उद्यमी प्रतिभा और साहस से प्रभावित थे और मस्क पूर्व राष्ट्रपति के विनियमन दृष्टिकोण तथा नौकरशाही मानकों में बदलाव की इच्छा की प्रशंसा करते थे। यह सहयोग उस समय अपने शिखर पर पहुंचा जब मस्क को 'डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट इफीसियेन्सी' का नेतृत्व सौंप दिया गया, जहां उन्होंने खर्च कम करने और संघीय ढांचे में खर्च को पुन: स्वरूप देने वाले सुधार शुरू किए। ट्रंप के नेतृत्व में बड़े सरकारी अनुबंधों और न्यूनतम हस्तक्षेपों के कारण मस्क के उद्यम फले-फूले। लेकिन जब मस्क ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप और रिपब्लिकन विधि-निर्माताओं की पैरवी वाले नए राजकोषीय विधेयक का विरोध कर दिया तो नाजुक संबंधों में दरार आने लगी। 'बिग ब्यूटीफुल बिल' कहे जाने वाले इस विधेयक में टैक्सों में व्यापक कटौती और खर्च में कमी के बावजूद राष्ट्रीय घाटे में भारी बढ़ोत्तरी होने तथा लाखों लोगों से स्वास्थ्य बीमा छिन जाने की आशंका पैदा हो गई है। मस्क ने इसे 'घृणित' बता कर चेतावनी दी कि इससे राजकोषीय अस्थिरता पैदा होगी। उनकी आलोचना से व्हाइट हाउस नाराज हो गया।

इलोन मस्क ने यह कह कर तनाव और बढ़ा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग आ सकता है। इसके जवाब में ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि यदि मस्क अगले चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं तो इससे उनके संघीय सरकार के संबंध टूट जाएंगे और उनको गंभीर 'परिणाम' भुगतने पड़ सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी बहुत असरदार है क्योंकि मस्क की कंपनियां संघीय सरकार से खासकर एयरोस्पेस व रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी पर अत्यधिक निर्भर हैं। मस्क के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से टकराव के वास्तव में बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मस्क द्वारा ट्रंप प्रशासन की आलोचना से भावी सरकारी अनुबंध मिलने में समस्यायें पैदा हो सकती हैं तथा उनके बिजनेसों को राजनीतिक बदले की भावना का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर उनके द्वारा संभवत: डेमोक्रेटों के समर्थन की स्थितियां हालिया वर्षों में उनके दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती हैं क्योंकि कंजरवेटिव लक्ष्यों और स्वरों के साथ उनका जुड़ाव बहुत गहरा हो गया था। दूसरी ओर ट्रंप को भी मस्क से टकराव के कारण तकनीक-समर्थक दक्षिणपंथियों के एक हिस्से का समर्थन खोना पड़ सकता है। लेकिन इस टकराव के बाद डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में पेश कर सकते हैं जो चुनौतियों से भयभीत नहीं होता है। ट्रंप और मस्क के बीच यह टकराव केवल व्यक्तिगत टकराव न होकर सरकारी शक्ति तथा निजी प्रभावशाली लोगों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। ट्रंप-मस्क संबंध खराब होने के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव वाशिंगटन से आगे तक दिख सकते हैं। इससे आने वाले वर्षों में अमेरिका में गठबंधन, चुनाव और नीतियां प्रभावित हो सकती हैं। मस्क से अलग होने के बाद देखना होगा कि ट्रंप का बड़े अमेरिकन उद्योगपतियों पर शिकंजा कैसा रहता है जिनको वे चीन और भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में विनिर्माण के लिए हतोत्साहित करते थे। यदि टैरिफ पर ट्रंप कुछ लचीलापन दिखाते हैं तो इससे विश्व अर्थव्यवस्था में पैदा मौजूदा अस्थिरता कम करने में सहायता मिलेगी।

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

बरसात की अनियमितता से करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में है। देर में बरसात से फसलें खराब होती हैं, भूमिगत जल घटता है तथा ग्लेशियर पिघलने का विनाशकारी असर होता है।

बीकेपी सिन्हा, अरविंद कुमार झा
(लेखक, पूर्व वन अधिकारी हैं)

भारत में कृषि मानसून से बहुत गहराई से जुड़ी है जो देश में वार्षिक बरसात में लगभग 70 प्रतिशत का जिम्मेदार है तथा इससे खेती की आधी जमीन प्रभावित होती है। लेकिन बढ़ती वैश्विक तापमान ने मानसून को लगातार अनुमान से परे किया है। अब मानसून का जल्दी या देर में आना सामान्य बात हो गई है और इसके साथ ही बरसात का पैटर्न भी बहुत अस्थिर हो गया है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात होती है, जबकि अन्य में लंबे समय तक सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती मानसूनी बरसात पर अत्यधिक निर्भर है। यहां किसान जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आमतौर से दो हेक्टर से कम जोत वाले छोटे किसान बहुसंख्य खेतिहर मजदूरों का भी हिस्सा होते हैं। अक्सर वे उपयुक्त सिंचाई, भंडारण सुविधाओं व वित्तीय सहायता से वंचित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप बरसात के समय में थोड़ी सी बाधा या फसल चक्र के महत्वपूर्ण समय पर अप्रत्याशित सूखेके कारण उनकी उपज का भारी नुकसान होता है। इससे पहले से ही संकटग्रस्त परिवार और कर्ज में डूब जाते हैं।

मानसूनी बरसात की विश्वसनीयता घटने के कारण किसान अपनी फसलों को जीवित रखने के लिए लगातार भूमिगत जल प्रयोग का प्रयास कर रहे हैं। सूखे के लंबे मौसमों में बोरवेल या ट्यूबवेल आवश्यक जीवनरेखा बन गए हैं। लेकिन यह निर्भरता तेजी से अपने आप में संकट बनती जा रही है। भूमिगत का अनियंत्रित और व्यापक दोहन तेजी से भूमिगत जल भंडार सूखा रहा है और यह खासकर उन क्षेत्रों में दिख रहा है जो पहले से ही भारी जल संकट का सामना कर रहे हैं। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड-सीजीडब्लूबी के अनुसार देश भर में 6,607 भूमिगत ब्लाकों में से 1000 की पहचान 'अत्यधिक शोषित' के रूप में की गई है। खासकर उत्तरपश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में स्थिति बहुत गंभीर है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दशकों से गहन खेती और खासकर अधिक पानी प्रयोग करने वाली गेहूं व धान की खेती के कारण भूमिगत जल भंडारों में भारी कमी आई है। सीजीडब्लूबी, 2023 आंकड़ों के अनुसार पंजाब के 153 ब्लाकों में से 87 प्रतिशत को अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक गंभीर या गंभीर ब्लाकों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार केवल 13 प्रतिशत ब्लाक ही 'सुरक्षित' श्रेणी में हैं। हरियाणा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है जहां 75.5 प्रतिशत से अधिक ब्लाक लगातार दोहन के लिए असुरक्षित माने गए हैं। भूमिगत जल का यह अत्यधिक दोहन खराब नीतिगत पहलों, सस्ती जल की अविश्वसनीय उपलब्धि तथा खराब निगरानी के कारण है। भूमिगत जल दोहन की पंपिंग पर सब्सिडी तथा पानी का अधिक प्रयोग करने वाली फसलों की खरीद नीति के कारण भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा मिला है।

भारत में बढ़ता जल संकट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर हिंदुकुश व हिमालयी क्षेत्रों में और गंभीर है। इस क्षेत्र में औसत तापमान 1951 के बाद से हर दशक में 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है जिसे कुछ नदी घाटियों में गर्मी बढ़ने की दर और भी तेज हो गई है। इसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघलने की गति में काफी तेजी आई है। वैज्ञानिक आंकलनों से संकेत मिलते हैं कि पिछले दशक में ग्लेशियर पिघलने की गति में 65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ग्लेशियरों के तेजी से पीछे हटने के कारण प्रमुख ग्लेशियर-पोषित नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु में पानी की कमी हुई है। ये नदियां सिंचाई, पेयजल और पनबिजली योजनाओं के लिए पानी उपलब्ध कराने के कारण उत्तर भारत की जीवनरेखा हैं और करोड़ों लोगों की जीवन प्रदान करती हैं। ऐतिहासिक रूप से ग्लेशियरों के पिघलने से आने वाला पानी नदियों का प्रवाह बनाए रखता है तथा भूमिगत जल सप्लाई को पोषित करता है। लेकिन ग्लेशियर पिघलने तथा इसके परिणामस्वरूप, खासकर सूखे मौसम में भूमिगत जल का संभरण धीमा हो जाताहै। इसे किसानों के समक्ष बढ़ी चुनौती पैदा होती है जो खासकर अपनी फसलों के लिए भूमिगत जल तथा नदियों के पानी पर निर्भर हैं। नदियों का प्रवाह धीमा होने से नहरों की सिंचाई व्यवस्था तथा पनबिजली उत्पादन बाधित होता है, जबकि ये दोनों भारत की कृषि उत्पादकता तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। सतही तथा भूमिगत जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण होने वाले नकारात्मक परिणाम मृदा लवणीकरण बढ़ने के रूप में सामने आते हैं जो खासकर अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में दिखते हैं। यह समस्या तटीय क्षेत्रों में गंभीर है जिनमें पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल हैं। यहां समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण खारी पानी ताजे पानी के स्रोतों और धान के खेतों में प्रवेश कर जाता है। केवल सुंदरबन में सिंचाई वाली लगभग 30 प्रतिशत भूमि इससे प्रभावित है। पूरे देश में लगभग 6.74 मिलियन हेक्टर भूमि लवण-प्रभावित के रूप में पहचानी गई है और यह क्षेत्र हर साल 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति बेलगाम जारी रही तो भारत की लगभग आधी कृषि योग्य भूमि 2050 तक प्रभावित हो सकती है।

मृदा की बढ़ती लवणीयता कृषि उत्पादकता घटा रही है तथा भूमि सुधार का खर्च बढ़ रहा है। अक्सर यह छोटे व सीमान्त किसानों की पहुंच से बाहर हो जाता है। इसके कारण बहुत से लोगों को खेती छोड़ कर वैकल्पिक आजीविका साधनों, जैसे झींगा पालन को अपनाना पड़ता है जिससे लवणीयता की समस्या और गंभीर होती है। भारत की आधी से अधिक श्रमशक्ति खेती पर निर्भर है, इसलिए उपजाऊ भूमि की कमी न केवल ग्रामीण आजीविका, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। भारत के 'डिजटींफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस' के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र तेजी से रेगिस्तानीकरण या क्षरण की ओर बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण जल एवं वायु से क्षरण है जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता तापमान मृदा की नमी छीन कर तथा पानी के लिए दबाव बढ़ा कर फसल चक्र के महत्वपूर्ण चरणों, जैसे फूल आने और अनाज के दाने बनने के समय संकट और बढ़ा रहा है। भारत के 'भोजन का कटोरा' कहे जाने वाला सिंधु-गंगा का मैदान जलवायु परिवर्तन के कारण उपज में 1 से 8 प्रतिशत कमी का सामना कर रहा है। पानी की उपलब्धता में कमी तथा सिंचाई के स्तर में कमी आने के कारण इसके परोक्ष प्रभावों से गेंहूं की उत्पादकता में तेजी से कमी आई है और यह नुकसान 4 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक है।

जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है क्योंकि उनको फलने-फूलने का मौका मिल जाता है। बढ़ते तामपान, बरसात के पैटर्न में परिवर्तन और नमी के स्तर में परिवर्तन से खेती में रोगों के प्रकार और उनकी व्यापकता में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ 2020 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में टिड्डी दलों के हमले के पीछे अरब प्रायद्वीप में असामान्य रूप से नम मौसम था जो सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा था। इससे फसलें बड़ी सीमा तक बरबाद हुई थीं। इन टिड्डी दलों ने लगभग 48,669 वर्ग किलोमीटर फसल नष्ट कर दी थी जिससे सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र था। इसके साथ ही खेती को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटों की संख्या में भी भारी वृद्धि हो रही है। इससे किसानों को मजबूर होकर ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है जिससे खेती की लागत बढ़ती है, स्वास्थ्य पर खतरा पैदा होता है तथा पर्यावरण को नुकसान होता है। परस्पर जुड़ी ये चुनौतियां कृषि संकट को बढ़ा रही हैं, किसानों की आजीविका तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। खेती के लगातार अनिश्चित होने के कारण बहुत से युवा सुरक्षित आजीविकाओं की तलाश में खेती छोड़ रहे हैं जिससे गांवों से शहरों में विस्थापन बढ़ा है। इससे शहरों की ढांचागत संरचना, सार्वजनिक सेवाओं और श्रम बाजारों पर असाधारण दबाव पड़ रहा है। इसके कारण सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है जो कभी-कभी कानून व्यवस्था की समस्या बन जाता है। यदि जलवायु परिवर्तन बेलगाम जारी रहा तो इससे निराशा बढ़ेगी तथा वंचित समुदायों और राज्य के बीच संबंध कमजोर होंगे जो आंतरिक स्थायित्व व राष्ट्रीय एकजुटता के लिए खतरा हो सकता है।

कर्म और दैवीय नियंत्रण

जो लोग लालची, कामुक, क्रोधित या घृणा करने वाले होते हैं, वे इन नारकीय भावनाओं से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं।

अजित विश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

हम जानते हैं कि ऑटोपायलट क्या है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी वाहन के मार्ग को स्वचालित रूप से नियंत्रित करती है, जिससे यह न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचालित हो सकता है। मैं इसका उपयोग हम मनुष्यों के लिए क्यों कर रहा हूँ? विश्वास करें या न करें, हमारे भौतिक शरीर वाहन हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद् गीता में श्लोक सं 18.61 में वर्णित किया है। वे कहते हैं, ईश्वर, वाहन (हमारे शरीर) में एक भाग के रूप में मौजूद है, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बड़ी तस्वीर देता हूँ। जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं, शीर्ष पर ईश्वर है। फिर, ईश्वरीय प्राधिकरण है, जो ईश्वर के पर्यवेक्षण के तहत काम करता है। वे भौतिक प्रकृति के कामकाज की देखरेख करते हैं, जो चलती और स्थिर चीजों के साथ दुनिया को जन्म देती है। और इसके कारण, विश्व चक्र चलता रहता है। (9.10) फिर, आत्मा वाले सभी जीवित प्राणी हैं, जो ईश्वर के अंश हैं। (15.7) और, बेशक, पेड़-पौधे आदि हैं। यह पूरी व्यवस्था ईश्वर के नियंत्रण में है, जो नियंत्रक है।

अब विषय पर लौटते हैं, हम ऑटोपायलट पर कैसे हैं? इसे समझने के लिए, हमें कर्मफल सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वभाव को जानना चाहिए। पहला सरल है- आप जो बोते हैं, वही काटते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचता है। यदि विचार गंभीर है, तो वह एक दिन इसे शुरू कर देगा। इसी तरह, कोई व्यक्ति एक छोटे से मजदूर के रूप में काम कर रहा है। उसे इसके लिए भुगतान मिलता है। तीसरा उदाहरण शब्दों का है। शिक्षक इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उन्हें किए गए प्रयास के लिए वेतन मिलता है। व्यक्तिगत स्वभाव थोड़ा अधिक जटिल मामला है। इसके लिए, तीन गुणों (मोड) की समझ महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह तीन गुणों से बना है, जो कि अच्छाई, जुनून और अंधकार हैं।

ईश्वर नियंत्रक है। ईश्वर चीजों को बदल सकता है। वह हमारे बुरे कर्मफलों से निपटने में मदद कर सकता है। साथ ही हमारे दोषपूर्ण स्वभाव को बदलने में भी हमारी सहायता कर सकता है।

ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। निश्चित रूप से, हमारे स्वभाव में भी विभिन्न अनुपातों में अच्छाई, जुनून और अंधकार शामिल हैं। अच्छे व्यक्ति में सत्वगुण का प्रतिशत अधिक और तमोगुण का प्रतिशत कम होगा। इसी तरह बुरे व्यक्ति में ठीक विपरीत अनुपात होगा, यानी तमोगुण अधिक और सत्वगुण कम। सामान्य व्यक्ति के स्वभाव में रजोगुण का प्रतिशत अधिक होता है। फिर, हमारा स्वभाव कैसे बनता है? जन्म-जन्मांतर में हम तीनों गुणों से जुड़ते हैं और वह हमारे स्वभाव में समा जाता है। और जब व्यक्ति मरता है, तो उसका संस्कार अगले शरीर में चला जाता है। उदाहरण के लिए, अच्छा व्यक्ति सत्वगुणी वस्तुओं से जुड़ता है। वह पौष्टिक भोजन खाता है। वह ऐसे कार्यक्रम देखता है, जिनमें प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक सामग्री होती है। वह ज्यादातर वही सुनता है जो शिक्षाप्रद होता है। इसके विपरीत, जो लोग लालची, कामुक, क्रोधित या घृणा करने वाले होते हैं, वे इन नारकीय भावनाओं से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं। भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन अलग-अलग द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इसलिए, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। (16.21) भगवान कृष्ण घृणा के बारे में बहुत सख्त हैं। भगवान कहते हैं, मैं उन ईर्ष्यालु, हानिकारक, क्रूर और निम्न श्रेणी के लोगों को बार-बार दुनिया में भेजता हूं, और वह भी राक्षसी योनि में। (16.19)

अब मैं आता हूं कि हम कैसे ऑटोपायलट पर हैं। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि पवित्र और अपवित्र कार्यों से उत्पन्न कर्मफल हमारे वर्तमान जीवन या भविष्य के जीवन में प्रकट होंगे। इससे कोई बच नहीं सकता। यहां तक कि भगवान भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

भगवान की चेतना में एक व्यक्ति के मामले में भगवान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी चेतना होने पर, आप मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। (18.58) हममें से बाकी लोगों को परिणामों का सामना करना होगा और उन्हें सहना होगा। कोई बच नहीं सकता, यही ऑटोपायलट है। हम इस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं। हमारे जीवन में ऑटोपायलट की दूसरी विशेषता बहुत अधिक गंभीर है। हम जो करते हैं या जिसके साथ जुड़ते हैं, उसके परिणामस्वरूप हमारी प्रकृति निरंतर विकसित होती रहती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कामुक होता है। वह अपने आप ही कामुक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाएगा। वह अपने पास दी गई स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके खुद को रोक सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वर्तमान प्रकृति जो कुछ भी निर्धारित करती है, उसे पूर्वचेत करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या सीखा है? कि हम असहाय रूप से ऑटोपायलट पर हैं। हमारे कर्मफल यह निर्धारित करेंगे कि हमारे साथ क्या होगा। हम आज जो करते हैं, वह काफी हद तक यह निर्धारित करेगा कि हमें अपने भविष्य और उसके बाद के जीवन में क्या मिलेगा। हमारे वर्तमान प्रयासों का कुछ प्रभाव होगा, लेकिन कोई विशेष महत्व नहीं होगा। क्या हम फंस गए हैं? वास्तव में नहीं। ईश्वर नियंत्रक है। जैसा कि पहले बताया गया है, ईश्वर चीजों को बदल सकता है। वह हमारे बुरे कर्मफलों से निपटने में मदद कर सकता है, साथ ही हमारे दोषपूर्ण स्वभाव को बदलने में भी हमारी मदद कर सकता है। आप परिणाम देखकर आश्चर्यचकित होंगे। हम अब हम ऑटोपायलट पर नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे जीवन पर अच्छा नियंत्रण होगा।

आप की बात

मोदी सरकार के 11 साल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में न केवल आर्थिक और वैश्विक स्तर पर प्रगति की है, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी साक्षी बना है। यह कालखंड भारतीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत को पुन: जाग्रत करने का युग बन गया है। विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ मोदी सरकार ने आधुनिक भारत के निर्माण को हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और सोमनाथ मंदिर के विस्तार जैसे कार्य न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के प्रतीक बन गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने के लिए योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना, आयुर्वेद को बढ़ावा देना और संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं को प्रोत्साहन दर्शाता है कि सरकार भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध है। जी-20 जैसे मंचों पर भारत को सांस्कृतिक विविधता और विरासत का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि भारत अपनी पहचान को लेकर गर्वित है। यह सांस्कृतिक उत्थान आत्मगौरव को बढ़ाने के साथ दुनिया में पहचान मजबूत करता है।

– **विभूति बुपक्या**, खाचरौद

न्यायपालिका पर विश्वास

भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता हैए जो संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का कार्य करती है। लेकिन हाल में न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और संभावित महाभियोग की चर्चा ने इस मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और गवई ने भले ही कोलेजियम प्रणाली की आलोचना स्वीकार की हो, लेकिन यह भी कहा कि इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त होना नहीं है। उसकी जवाबदेही तटस्थ एवं निष्पक्ष जन-भावनाओं के प्रति है। महाभियोग की जटिल प्रक्रिया और बेहद सीमित सफल उदाहरण बताते हैं कि न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़नी चाहिए। न्यायपालिका को खुद अपने भीतर एक स्वतंत्र जांच प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और लोक-शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सके। सोशल मीडिया से स्पष्ट है कि जनता में अब इस संस्था के प्रति विश्वास डगमगा रहा है। इसे बहाल करने के प्रभावी कदम तत्काल उठाना जरूरी हो गया है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

विपक्ष की बौखलाहट

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी कुनबे का सफाया किया, काफी आतंकियों को मौत के घाट उतारा और आतंकी अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए। यह सब देश-दुनिया ने देखा। लेकिन यह बात कुछ विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही। ये नेता अनर्गल बयानबाजी कर युद्ध में भारतीय सैनिकों की सफलता के प्रमाण मांगने की पूर्वाग्रही मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। विपक्ष की यह बौखलाहट नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनय और सेना की उल्लेखनीय उपलब्धियों की जनता में होने वाली प्रशंसा और उसके कारण भाजपा के बढ़ते जनाधार के कारण है। आज विपक्ष के ऐसे नेता भले ही खामोश हो जो हर हालत में भारत-पाक दोस्ती की पैरोकारी करते रहे हों, लेकिन वे आपरेशन सिंदूर स्थगित रखने को नरेन्द्र मोदी का सरेंडर बता रहे हैं। वे भारतीय विदेश नीति को विफल बता रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यदि 1971 में सोवियत संघ भारत के पक्ष में बार-बार वीटो न करता तो बांग्लादेश की मुक्ति संकट में पड़ जाती। वे इस बात का भी जवाब नहीं दे सकते हैं कि पाकिस्तान की लगभग एक तिहाई सेना के आत्मसमर्पण के बावजूद वे पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस क्यों नहीं ले सके।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह

कश्मीर की प्रगति

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पुल तथा नई ट्रेनों का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर को न केवल भारत से अच्छी तरह जोड़ दिया है, बल्कि इससे उसकी आर्थिक प्रगति का रास्ता भी और विस्तृत हो गया है। अब कश्मीर की वादियों से निकल कर ताजगी भरा सेब, चेरी, केसर और अन्य मेवे बहुत जल्दी से दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश जुड़ जायेगा। एफिल टावर से भी ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारतीय इंजीनियरों और कुशल कर्मियों के साथ ही सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ठीक ही कहा है कि जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वह नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया। यह पुल, नई रेल लाइनें व जम्मू कश्मीर को तेज आर्थिक प्रगति पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए एक सपने की तरह है। कश्मीर की इस प्रगति को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इच्छा भी जल्द पूरी होगी कि पाक-अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में मिलने की मांग करेंगे।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।